● वर्ष-3
● अंक-98
रायपुर, शनिवार
02 दिसंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।
समाचार पचीसा
राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› एप्स डेवलपर सर्वश्रेष्ठ कैरियर ...

लॉस एंड डैमेज फंड के संचालन की मोदी ने की सराहना, बोले

नई आशा का हुआ संचार

दुबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दो सप्ताह के सीओपी28 जलवायु सम्मेलन के उद्घाटन के कुछ ही क्षण बाद, शुक्रवार को 475 मिलियन डॉलर के लॉस्ट एंड डैमेज फंड को चालू करने के यूएई राष्ट्रपति पद के ऐतिहासिक फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि कल हुई लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित करने के निर्णय का भारत स्वागत करता है। इससे सीओपी28 समिट में नई आशा का संचार हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि सीओपी28 समिट से क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़े अन्य विषयों पर भी ठोस परिणाम निकलेंगे।

ग्लोबल साउथ का जिक्र

मोदी ने कहा कि जी20 में इस बात पर सहमति बनी कि जलवायु कार्रवाई के लिए 2030 तक कई ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। ऐसा जलवायु वित्त जो उपलब्ध हो, सुलभ हो और किफायती हो। मुझे उम्मीद है कि यूएई की जलवायु वित्त रूपरेखा पहल के साथ इस पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी आवश्यक है। ग्लोबल साउथ के देशों की अपेक्षा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देश यथासंभव उनकी मदद करें। यह स्वाभाविक एवं उचित है।

जलवायु परिवर्तन सर्वोच प्राथमिकता

नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को अपनी (जी20) अध्यक्षता की नींव बनाया और सामूहिक प्रयासों से हम कई मुद्दों पर सहमति बनाने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सहित वैश्विक दक्षिण के देशों की जलवायु परिवर्तन में कम भूमिका रही है। लेकिन उन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत अधिक है। संसाधनों की कमी के बावजूद ये देश जलवायु कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

ऋषि सुनक से मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीओपी28 दुबई शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ उत्कृष्ट बातचीत हुई। भारत-ब्रिटेन के बीच की मित्रता आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद करेगी। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीओपी28 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने दोस्तों, ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड कैमरन और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से मिलकर खुशी हुई। मैं सतत विकास की दिशा में काम करने के उनके जुनून की सराहना करता हूं।

एग्जिट पोल को कमलनाथ ने बताया भाजपा का षडयंत्र, रणदीप सुरजेवाला की चेतावनी

भोपाल। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को 230 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन उसे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि राज्य में उसी के सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने एग्जिट पोल को ही साजिश बता दिया और अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने को भी कह दिया। दूसरी और एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने अफसरों को भी चेतावनी दे दी है।

कमलनाथ का बयान

कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया

जाए। उन्होंने कहा कि यह षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठनों के प्रमुख और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी अपने-अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है।

सुरजेवाला की चेतावनी

सुरजेवाला ने कहा कि मध्यप्रदेश में ज्यादातर सर्वे एजेंसियां कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की जीत दिखा रही हैं, मगर भाजपा सिर्फ उस सर्वे पर भरोसा कर रही है जिस पर खुद सर्वे दिखाने वाला चैनल भरोसा नहीं कर रहा हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा मतगणना वाले दिन प्रशासन पर दबाव बनाने की बदनीयती रखती है। जिसका उदाहरण हमें बालाघाट की पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी करने की कोशिश से साफ़ नज़र आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्यप्रदेश में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वह अधिकारी भी जान लें जो बदनीयती से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की सोच रहे हैं। क़ानून के हाथ बहुत लंबे हैं। क़ानून तोड़ने वालों के खिलाफ़ कांग्रेस की अगली सरकार एफआईआर भी दर्ज करेगी और प्रशासनिक कार्यवाही भी।

क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल

पोल ऑफ पोल्स ने अनुमान लगाया है कि भाजपा राज्य की 230 सीटों में से 124 सीटें जीतेगी जबकि कांग्रेस 102 सीटों पर विजयी होगी। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 116 है। न्यूज 24-टुडेज चाणक्य ने राज्य में भाजपा के लिए स्पष्ट, आरामदायक जीत की भविष्यवाणी की है। सत्ताधारी पार्टी के लिए एग्जिट पोल का पूर्वानुमान 151 है, जबकि कांग्रेस के 74 पर सिमटने का अनुमान है, जो बहुमत के आंकड़े से 40 से अधिक सीटें कम है। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया ने कहा है कि भाजपा को कांग्रेस के 68-90 के मुकाबले 140-162 सीटें मिलने की उम्मीद है। इंडिया टीवी-सीएनएक्स ने भी बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि पार्टी 140-159 सीटें जीतेगी, जबकि कांग्रेस 70 से 89 के बीच सीमित रहेगी। हालाँकि, टीवी 9 भारतवर्ष-पोलस्ट्रैट की भविष्यवाणियाँ कांग्रेस के पक्ष में हैं, जिसमें पार्टी को 111 से 121 सीटों के बीच जीतने और भाजपा को 106-116 तक सीमित रहने का अनुमान लगाया गया है।

रायपुर में रिंकू के बाद रवि-अक्षर का कमाल

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हराया; सीरीज भी जीता

रायपुर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 में 20 रन से हरा दिया और पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 174 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम सात विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी और मैच के साथ सीरीज भी हार गई। सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच तीन दिसंबर को बंगलूरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत के लिए सबसे ज्यादा 46 रन रिंकू सिंह ने बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 37 और जितेश शर्मा ने 35 रन का योगदान दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 32 रन बनाकर आउट हुए।

ऑस्ट्रेलिया के लिए बेन ड्वारिशस ने तीन और तनवीर सांघा-जेसन बेहरनडॉर्फ ने दो-दो विकेट लिए। एरोन हार्डी को एक विकेट मिला। इस मुकाबले में टीम इंडिया आखिरी दो ओवर में सिर्फ 13 रन बना पाई और पांच विकेट गंवा दिए। इसी वजह से भारत का स्कोर 200 रन के करीब नहीं पहुंच सका। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा नाबाद 36 रन कप्तान मैथ्यू वेड ने बनाए। ट्रेविस हेड ने 31 और मैथ्यू शॉर्ट ने 22 रन का योगदान दिया। बेन मैकडरमॉट और टिम डेविड ने 19-19 रन का योगदान दिया। भारत की जीत में सबसे ज्यादा योगदान स्पिन गेंदबाजों का था। ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती चार विकेट भारतीय स्पिनर्स ने ही लिए थे। अक्षर पटेल ने तीन और दीपक चाहर ने दो विकेट लिए। रवि बिश्नोई और आवेश खान को एक-एक विकेट मिला। हालांकि, भारतीय स्पिनर्स ने बेहद कंजूसी के साथ गेंदबाजी की और अक्षर-रवि ने मिलकर आठ ओवर में 33 रन दिए और चार विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने अंतिम एकादश में बदलाव करते हुए श्रेयस अय्यर, जितेश शर्मा, दीपक चाहर और मुकेश कुमार को शामिल किया। जायसवाल को अपना खाता खोलने में छह गेंदों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर चौके के साथ अपना खाता खोला। उन्होंने तेज खेलना शुरू किया। पारी का तीसरा ओवर कर रहे ड्वारिशस के ओवर में उन्होंने तीन चौके लगाकर 12 रन बटोरे। 34 गेंदों में भारत के 50 रन पूरे हो गए थे, लेकिन इस बीच जायसवाल (37) हार्डी की गेंद को छक्का मारने के प्रयास में कैच दे बैठे। पारी का आठवां ओवर कर रहे सांघा ने श्रेयस अय्यर (08) को ग्रीन के हाथों कैच आउट कराकर मेजबान टीम को बड़ा झटका दिया। अय्यर इस सीरीज में पहला मैच खेल रहे थे।

प्रमुख समाचार

भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन जाने की ट्रेनिंग देगा नासा

नई दिल्ली। अमेरिका अगले वर्ष भारत के एक एस्ट्रोनॉट को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस भारतीय एस्ट्रोनॉट को इसरो द्वारा चयनित किया जाएगा। इस एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष यात्रा और स्पेस स्टेशन में काम की ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी इसरो की होगी। ये जानकारी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने दी है। वो पूर्व भारतीय एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा से मुलाकात कर रहे थे। इस मुलाकात के दौरान बिल नेल्सन ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच स्पेस इंडस्ट्री को लेकर कई समझौते भी हुए है। बता दें कि बिल नेल्सन बेंगलुरु में निसार सैटेलाइट की जांच-पड़ताल के लिए पहुंचे थे। नासा-इसरो एसएआर को निसार सैटेलाइट नाम दिया गया है। इस सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा में तैनात किया जाना है। ये सैटेलाइट एक एसयूवी के आकार की होगी। माना जा रहा है कि ये सैटेलाइट अगले वर्ष की पहली तिमाही में लॉन्च की जा सकती है। निसार सैटेलाइट का काम होगा धरती का नक्शा बनाना जिस काम को पूरा करने में इसे 12 दिन का समय लगेगा। इस नक्शे में सैटेलाइट हर पहलू का ध्यान रखेगा। इसमें बर्फ की लेयर, ग्लेशियर, जंगल, समंदर का जलस्तर, भूजल, प्राकृतिक आपदाएं जैसे- भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन संबंधित जानकारी देना शामिल होगा।

फिरोजाबाद बनेगा चंद्रनगर, निगम से प्रस्ताव पास, योगी सरकार लेगी अंतिम फैसला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के एक और जिले का नाम बदलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम अब चंद्रनगर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया।

निगम की बैठक में 12 में से 11 कार्यकारिणी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। इससे 2 साल पहले जिला पंचायत की बैठक में भी यह प्रस्ताव पास हो गया है। फिरोजाबाद सुहाग की नगरी के रूप में जाना जाता है। इस प्रस्ताव को अब शासन के पास भेज दिया गया है जहां इसके नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पेश किये गये। कर अधिकारी नीरज पटेल ने फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर करने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। वार्ड संख्या 61 से समाजवादी पार्टी (सपा) के पार्षद मोहम्मद रिहान ने सबूत पेश करने का सुझाव दिया कि फिरोजाबाद को पहले चंद्रनगर कहा जाता था।

सपा पर बरसे योगी गलत तथ्य पेश करने का लगाया आरोप, बोले-

यूपी के प्रति लोगों की बदली धारणा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि डबल इंजन सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य के प्रति धारणा बदल गई है और आज लोग यूपी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।

मुख्यमंत्री ने यह बयान विधानसभा को संबोधित करते हुए दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार और पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मैं एक आम आदमी और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर यह कह सकता हूं कि राज्य के प्रति धारणा बदल गई है। आज लोग यूपी की ओर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सीएम योगी ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी (समाजवादी पार्टी) सरकार विधानसभा में गलत तथ्य पेश करती थी और लोग उनके कुकर्मों को नहीं भूले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार रही। आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया है।

चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी कंगना रनौत

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की राजनीति में आने की खबरें लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है। कंगना रनौत के अपने कुछ बयानों से हिंट भी दिया है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर क्या अपडेट है, इसको लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। कंगना रनौत, जिन्हें

आखिरी बार तेजस में देखा गया था, ने भाजपा के लिए चंडीगढ़ में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीतिक क्षेत्र में शामिल होने की अफवाहों का जवाब दिया है। अफवाह थी कि वह संभावित रूप से किरण खेर की जगह लेंगी। एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में संकेत दिया गया कि बीजेपी के अंदरूनी लोग कंगना को किरण खेर का रिप्लेसमेंट मान रहे हैं। राजनीति में उनके संभावित प्रवेश ने बड़े पैमाने पर अटकलें लगाईं, जो उनके करियर में अभिनय से शासन में संभावित परिवर्तन का प्रतीक था। कंगना रनौत ने 1 दिसंबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए उनके राजनीति में प्रवेश करने की वायरल खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने एक हिंदी समाचार रिपोर्ट साझा करते हुए दावों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि उनके लिए जिम्मेदार शीर्षक गलत था, इस बात पर जोर देते हुए कि यह उनका बयान नहीं था।

मिजोरम विधानसभा चुनाव- मतगणना अब चार दिसंबर को होगी

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना अब निर्धारित समय से एक दिन बाद यानी चार दिसंबर को होगी। पहले मतगणना तीन दिसंबर (रविवार) को होनी थी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह निर्णय मतगणना की तारीख में बदलाव के विभिन्न हलकों के अनुरोध के बाद इस आधार पर लिया गया कि रविवार का दिन ईसाई-बहुल

राज्य मिजोरम के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसने कहा, "आयोग ने इन अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए, मिजोरम विधानसभा के आम चुनाव के लिए मतगणना की तारीख को तीन दिसंबर, 2023 (रविवार) से संशोधित करके चार दिसंबर, 2023 (सोमवार) करने का निर्णय लिया है।" पहले चार अन्य राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ ही मिजोरम में भी मतगणना तीन दिसंबर को होनी थी। इन सभी राज्यों में पिछले महीने विधानसभा चुनाव हुए थे। इसने कहा, "आयोग ने इन अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए, मिजोरम विधानसभा के आम चुनाव के लिए मतगणना की तारीख को तीन दिसंबर, 2023 (रविवार) से संशोधित करके चार दिसंबर, 2023 (सोमवार) करने का निर्णय लिया है।"

बाइडन को शोक संदेश भेजकर शी जिनपिंग ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ

चीन और अमेरिका के बीच का तनाव किसी से छुपा नहीं है। एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त हुआ करते थे। चीन को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं अमेरिका का ही हाथ था। अमेरिका को लगा कि चीन और अमेरिका साथ मिलकर काम करेंगे लेकिन चीन व्यापार के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया। आज दोनों देशों के बीच की जो वरचस्व की जो जंग है वह पूरी दुननिया देख रही है। कुछ लालच में की गयी अमेरिका की गलतियों ने ही चीन को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। दोनों देशों के बीच हमेशा तनाव जैसी ही स्थिति रहती है। ऐसे में इस बार चीन के एक एक्शन से लग रहा है उसने अमेरिका की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है।

ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री और 1972 में चीन और अमेरिका के बीच तनाव कम करने में एक प्रमुख खिलाड़ी हेनरी किसिंजर के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, किसिंजर का बुधवार को 100 साल की उम्र में कनेक्टिकट स्थित उनके घर पर निधन हो गया।

शी ने चीनी सरकार और लोगों की ओर से, साथ ही उनके नाम पर, किसिंजर के परिवार को अपनी गहरी सहानुभूति और संवेदना भेजीं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, शी जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा कि किसिंजर एक विश्व प्रसिद्ध रणनीतिकार और चीनी लोगों के पुराने और अच्छे दोस्त थे। शी ने कहा, एक उत्कृष्ट रणनीतिक दृष्टि के साथ, किसिंजर ने चीन-अमेरिका संबंधों को सामान्य बनाने में ऐतिहासिक योगदान दिया, जिससे न केवल दोनों देशों को फायदा हुआ बल्कि दुनिया भी बदल गई। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, शी ने आगे कहा कि किसिंजर ने चीन-अमेरिका संबंधों के विकास को बढ़ावा देने और दोनों लोगों के बीच दोस्ती को बढ़ाने के लिए इसे अपना आजीवन लक्ष्य बना लिया था और उनका नाम हमेशा चीन-अमेरिका संबंधों के साथ जुड़ा रहेगा। 1971 में किसिंजर की चीन की गुप्त यात्रा के बाद, अगले वर्ष तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन की ऐतिहासिक यात्रा की नींव रखी गई और अंततः अमेरिका-चीन संबंधों का सामान्यीकरण भी उनके द्वारा संभव हुआ। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी में पैदा हुए शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने तब से चीन की 100 से अधिक यात्राएं की हैं, सबसे हालिया यात्रा जुलाई 2023 में हुई। किसिंजर की मृत्यु की घोषणा उनकी परामर्श फर्म द्वारा एक बयान में की गई, जिसमें कारण का उल्लेख नहीं किया गया। द वाशिंगटन के अनुसार, एक विद्वान, राजनेता और सेलिब्रिटी राजनयिक किसिंजर ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों - रिचर्ड एम निक्सन और गेराल्ड फोर्ड के प्रशासन के दौरान और उसके बाद एक सलाहकार और लेखक के रूप में अमेरिकी विदेश नीति पर अद्वितीय शक्ति रखी, जिन्होंने वैश्विक राजनीति और व्यापार को आकार देने वाली राय साझा की। रिपोर्ट पोस्ट करें. हेंज अल्फ्रेड किसिंजर का जन्म 27 मई, 1923 को जर्मनी के फर्थ में हुआ था। वह 12 वर्ष के थे जब नूर्नबर्ग कानूनों ने जर्मनी के यहूदियों से उनकी नागरिकता छीन ली थी। न्यूयॉर्क में एक रिश्तेदार द्वारा प्रायोजित, किसिंजर और उनका परिवार अगस्त 1938 में जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद वह हेनरी बन गए।

द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, एक ही समय में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अमेरिकी विदेश मंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में, उनका अमेरिकी विदेश नीति पर नियंत्रण था, जिसकी तुलना शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति ने की हो जो राष्ट्रपति नहीं था।

किसिंजर और वियतनाम के ले डक थो को गुप्त वार्ता के लिए नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया गया, जिसके कारण 1973 का पेरिस समझौता हुआ और वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना की भागीदारी समाप्त हो गई। 1973 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद उनकी शटल कूटनीति ने इज़राइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच संबंधों को स्थिर करने में मदद की। अपने जर्मन उच्चारण, तीक्ष्ण बुद्धि, उल्लू जैसी शक्ल और हॉलीवुड में सामाजिक मेलजोल के उत्साह के कारण उन्हें तुरंत दुनिया भर में पहचान मिल गई।

दंतेवाड़ा में नक्सली पीएलजीए सप्ताह का बड़ा असर, वाल्टेयर रेल सेवा बाधित

दंतेवाड़ा। वाल्टेयर रेलमंडल ने नक्सलियों की पीएलजीए सप्ताह के दौरान दंतेवाड़ा से किरंदुल रेल नहीं चलाने का फैसला किया है।आपको बता दें कि नक्सलियों ने हाल ही में भांसी स्टेशन के पास 14 वाहनों में आगजनी की थी।जिसके बाद रेलवे ने ट्रेनों को ना चलाने का फैसला लिया है।आपको बता दें कि नक्सली 2 से 8 दिसंबर के बीच पीएलजीए सप्ताह मना रहे हैं।इसी वजह से रेलवे ने दंतेवाड़ा से किरंदुल के बीच 42 किलोमीटर तक यात्री ट्रेनों को नहीं चलाने का फैसला किया है।

वाल्टेयर रेलमंडल ने जारी किए निर्देश- वाल्टेयर रेलमंडल से जारी निर्देश में 29 नवंबर से 03 दिसंबर तक यात्री ट्रेनों को दंतेवाड़ा में स्थगित कर वहीं से विशाखापत्तनम के बीच चलाने के लिए कहा गया है। इस दौरान दंतेवाड़ा-किरंदुल के बीच यात्री रेल सेवा बंद रहेगी। समीक्षा के बाद 04 दिसंबर से दंतेवाड़ा-किरंदुल के बीच यात्री रेल सेवा फिर से शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा।इस बीच यदि रेलवे को सुरक्षा को लेकर थोड़ा भी अंदेशा रहा तो वो यात्री ट्रेनों को चलाने में थोड़ा समय ले सकता है।फिलहाल ट्रेनों को 3 दिसंबर तक रोकने का फैसला किया गया है।

कब हुई थी नक्सली वारदात- आपको बता दें कि चार दिन पहले भांसी स्टेशन के पास 40 से 50 हथियारबंद लोग पहुंचे थे। यहां एक प्राइवेट कंपनी निर्माण कार्य कर रही थी।इसी दौरान इन लोगों ने वाहनों और मशीनों को निशाना बनाया। करीब 14 वाहनों और मशीनों को आग के हवाले कर दिया

गया।आगजनी में ट्रक,अर्थ मूविंग के साथ पोकलेन मशीनों में आग लगाई गई थी।जिन मशीनों में आग लगाई गई थी वो दंतेवाड़ा और बचेली के बीच सड़क निर्माण का काम कर रही थी।जिसमें पानी का टैंकर भी था। घटना के बाद भांसी स्टेशन हाउस अधिकारी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची थी।टीम ने मौके का मुआयना करने के बाद इसे नक्सली घटना बताया था।साथ ही साथ जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है।

नक्सलियों ने लगाए पोस्टर, दो से आठ तक पीएलजीए की वर्षगांठ मनाने का ऐलान

कांकेर। कांकेर के पखांजुर अनुविभाग के बांदे थाना क्षेत्र के बेलगाल चौक पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं । नक्सलियों ने दो दिसंबर से आठ दिसंबर तक पीएलजीए की 23वीं वर्षगांठ को देश भर में मनाने की बात कही। नक्सलियों ने इजरायल के युद्ध के खिलाफ फिलिस्तीन की जनता को मुक्त करने के आंदोलन को समर्थन करने की बात लिखी है, वहीं क्रांतिकारी जनताना सरकारों को बचने एवं मजबूत करने की बात बैनर में लिखा है। नक्सली लगातार क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं वहीं परतापुर एरिया कमेटी ने स्टेट हाइवे क्रमांक 25 के बेलगाल चौक में बैनर पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी ली है,वहीं क्षेत्र में लगातार सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान तेजी से चल रहा है। वहीं, दूसरी तरफ पीव्ही 62 में मोबाइल टावर में नक्सलियो ने आग लगा दी है। नक्सलियों का तांडव यहीं खत्म नहीं हुआ है, संगम जाने वाली पक्की सड़क को भी जगह-जगह से काटकर नक्सलियों ने उखाड़ा दिया है और भारी मात्रा में पर्चे फेंके हैं। कल दो दिसंबर से नक्सलियों का पीएलजीए सप्ताह शुरू हो रहा है, जिसे लेकर नक्सली तांडव मचा रहे हैं। छोटे बेठिया और बांदे थानाक्षेत्र में जमकर मचाया गया है।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने जनअदालत लगाकर उपसरपंच की हत्या की

कांकेर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पीएलजीए सप्ताह शुरू होने से एक दिन पहले बड़ी नक्सली घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों के परतापुर एरिया कमेटी ने ग्राम पंचायत कंदाड़ी के उपसरपंच की हत्या कर दी। नक्सलियों ने जनअदालत लगाकर उपसरपंच रामशु कचलामी को मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों ने उपसरपंच पर ग्रामीण की हत्या कर नक्सलियों को बदनाम करने की साजिश रचने, नक्सलियों को बहलाकर सरेंडर करने और पुलिस मुखबिरी जैसे कई आरोप उपसरपंच रामशु कचलामी पर लगाए और उसकी निर्मम हत्या कर दी। अचिन पुर गांव के पास नक्सलियों ने पर्चा फेंक कर घटना की जिम्मेदारी ली है।मारे गए उप सरपंच का शव अब तक बरामद नही किया गया है। पीएलजीए सप्ताह शुरू होने के 1 दिन पहले ही नक्सलियों ने

कांकेर जिले में भारी तांडव मचा रखा है। कंदाड़ी में उपसरपंच की हत्या के बाद नक्सलियों ने पखांजूर में जमकर तांडव मचाया। पखांजूर क्षेत्र के अचिनपुर और बुरका गांव में नक्सलियों ने सड़क खोदकर रोड जाम कर दिया है जिससे आने जाने वालों को काफी मुश्किल हो रही है। बुरका गांव में लगे निजी कंपनी के टावर को नक्सलियो ने आग के हवाले कर दिया है। इसके अलावा बेलगाल चौक समेत विभिन्न जगहों पर नक्सलियो ने भारी मात्रा में बेनर पोस्टर चस्पा किया है।जिसमे 2 दिसम्बर से 8 दिसंबर तक पूरे देशभर में पीएलजीए सप्ताह जोरशोर से मनाने की अपील की गई है। कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने पूरे घटना की पुष्टि की है। बंदे थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलगांव में नक्सलियों ने भारी मात्रा में बैनर - पोस्टर लगाए है। बैनर पोस्टर में पीएलजीए की 23 वी वर्षगांठ को गाजा पर इजराइल युद्ध के खिलाफ फिलिस्तीन जनता के मुक्ति आंदोलन के समर्थन को वर्षगांठ मानने का जिक्र किया है। साथ ही गुरिल्ला युध्द तेज करने और आरएसएस भाजपा का भी बैनर में जिक्र है। पीएलजीए सप्ताह को नक्सली शहीद दिवस के रूप में मनाते है। पीएलजीए का पूरा मतलब पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी है। पीएलजीए सप्ताह के दौरान नक्सली कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में लगे रहते हैं। पीएलजीए सप्ताह नक्सली अपने संगठन के मारे गए सदस्यों को याद करते हुए हर साल 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक एक सप्ताह शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं।

बीजापुर में बदलेगी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा विभाग की टीम पहुंची माड़

स्कूलों में देखी व्यवस्था, भवन निर्माण का लिया निर्णय

बीजापुर। जिले में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और दूरस्थ इलाके में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कवायद के बीच जिला शिक्षा अधिकारी के साथ शिक्षा विभाग की टीम माड़ इलाके में पहुंची। यहां सातवा ग्राम पंचायत के एहकेली और पल्लेवाया स्कूल का निरीक्षण कर व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। दोनों जगहों पर स्कूल भवनविहिन है। यहां नदी का पानी कम होने के बाद भवन निर्माण का निर्णय लिया गया।

बीते दिन जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल, एपीसी जाकिर खान, एमवी राव, बीआरसी विजय ओयम ने जिले के अंतिम छोर नारायणपुर जिले के सरहद में बसे पल्लेवाया का दौरा किया। यह इलाका बीजापुर जिला मुख्यालय से दंतेवाड़ा जिले के तुमनार से होते हुए नारायणपुर जिला के सरहद में बसा हुआ है, जिसकी दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर है। बीजापुर तुमनार तक चौपहिया वाहन से 2 घंटे के यात्रा के बाद गुणनेमार्ग से इंद्रावती नदी की बाधा को लकड़ी के नाव के सहारे पार कर पैदल करकावाड़ा एहकेली पहुंचने में 4 घंटे लग गए तब जाकर माड़ इलाके की शिक्षा से विभाग की टीम रूबरू हो पाई।

सलवा जुडूम के बाद यह इलाका

वीरान और विस्थापित हो चुका था, जो अब सरकार के संवेदनशील प्रयासों से फिर बसने लगा है। 2005 में स्कूल बंद होने के बाद बीते साल यहां स्कूल फिर से शुरू किया गया और स्थानीय नौजवानों के जरिए तालीम के रास्ते फिर से खोले गए। विपरीत हालतों और सुविधाओं के अभाव में इन खोले गए स्कूलों की जमीनी हकीकत देखना शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बीहड़ दुर्गम और अतिसंवेदनशील इलाके के रूप में पहचान बना चुका माड़ एरिया आज भी सामान्य रूप से आवा जाही के लिए सुगम और सुरक्षित नहीं है। इन हालातों में इस चुनौती को पार कर शिक्षा विभाग की टीम 25 किलोमीटर पैदल चलकर करकावाडा, एहकेली, पल्लेवाया पहुंची और स्कूलों का निरीक्षण किया।

भवन और शुद्ध पानी की आवश्यकता, मिड डे मील का समुचित प्रबंधन, बच्चों की नियमित और शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ न्यूनतम अधिगम दक्षाताओं को विकसित करने के कार्य योजना को मूर्त रूप देने रणनीति बनाई गई। शिक्षा दूत, ग्रामीणों से मिलकर चुनौतीयों की पहचान कर उसे दूर करने आपसी सामंजस्य से कार्य करने पर बल दिया गया। पल्लेवाया से नारायणपुर जिला का पीडियाकोट महज 2 किलो मीटर दूर है, जहां 50 सीटर बालक आश्रम संचालित है। वहां पहुंचकर अधीक्षक से मुलाकात कर शाला संचालन की स्थिति का जायजा लिया गया। यहां से शाम को रवानगी के बाद टीम 7 बजे रात में इंद्रावती नदी के मुहाने पर पहुंच पाई और अंधियारे में फिर लकड़ी के नाव के सहारे नदी पार कर तुमनार पहुंचने के बाद चौपहिया वाहन से जिला मुख्यालय पहुंच कर अपने अभियान को पूरा किया।

भवन निर्माण बड़ी चुनौती

माड इलाका संवेदनशील और दुर्गम होने से निर्माण कार्य एक बड़ी चुनौती है। इंद्रावती नदी में पुल नही होना किसी भी निर्माण के लिए बड़ी बाधा है। इलाके में स्कूल झोपड़ी और अस्थाई शेड में चल रहे हैं। जिला प्रशासन की प्राथमिकता यहां भवन निर्माण कर बेहतर व्यवस्था देने की है, जिसके बाद इस इलाके में शिक्षा व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।

शिक्षा में सुधार के लिए मॉनिटरिंग आवश्यक : डीईओ

अतिसंवेदनशील माड़ इलाके में दौरे को लेकर डीईओ बीआर बघेल ने बताया, भैरमगढ़ का माड़ इलाका अत्यंत दुर्गम और अतिसंवेदनशील इलाका है। यहां मॉनिटरिंग करना और व्यवस्था बनाए रखना चुनौती है। कलेक्टर की मंशा अनुरूप शिक्षा विभाग की टीम ने एहकेली पल्लेवाया का दौरा किया और शिक्षा व्यवस्था का आकलन कर आगामी दिनों में सुधार की रणनीति बनाई गई है।

पुलिस क्या सिर्फ रसूखदारों के लिए ही काम करती है: हाई कोर्ट

■ **बिलासपुर पुलिस पर बड़ी टिप्पणी**

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि रसूखदारों के लिए पुलिस रात 2 बजे तक सक्रिय रहती है और उनका काम जल्दी करती है, लेकिन गरीबों के लिए पुलिस को क्या हो जाता है। कोर्ट के तल्ख टिप्पणी से एक बार फिर पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान लग गया है।

पूरा मामला बिलासपुर का है। 1 जून 2022 को जमीन दलालों की प्रताड़ना से तंग आकर सिद्धांत नागवंशी ने आत्महत्या कर ली थी।सकरी थाना क्षेत्र में रहने वाले वीरेंद्र नागवंशी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उनके बेटे सिद्धांत नागवंशी ने जमीन दलालों की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी की थी। पिता वीरेंद्र नागवंशी ने बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ सकरी थाने में शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। लेकिन डेढ़ साल बाद भी पुलिस ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और कोई जांच और ना ही किसी और तरह की कार्रवाई की है। कार्रवाई नहीं होने की वजह से मृतक युवक के पिता ने हाईकोर्ट में अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर कर बताया कि पुलिस कार्रवाई करना नहीं चाहती।

हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए पुलिस को जमकर फटकार लगाई और आदेश दिया

है कि सकरी थाना प्रभारी प्रकरण में अगली सुनवाई में शपथ पत्र पेश करते हुए हाजिर होने का आदेश दिया। मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि लगता है पुलिस जानबूझकर मामले की जांच नहीं करना चाहती। कोर्ट ने प्रतिवादी के वकील से कहा कि थानेदार को नौकरी करनी है कि नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया की शिकायत के बाद से लेकर अभी तक पुलिस ने मामले में क्या जांच की, किसका बयान लिया, पूरी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट करें।

पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के साथ ही जमीन दलालों के द्वारा प्रताड़ना से लोगों की जान जाने के मामले में कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जानबूझकर कार्रवाई नहीं करना चाहती थी और इसलिए पूरे मामले को डेढ़ साल तक लटकाया गया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस रसूखदारों के मामले में पूरी रात काम कर रिजल्ट पर तत्काल पहुंचती है, वहीं गरीब लोगों के लिए पुलिस यह कर्तव्य क्यों नहीं निभाती। मामले में कोर्ट ने राज्य शासन, एसपी बिलासपुर को भी नोटिस जारी किया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बैकुंठपुर जिला अस्पताल हुआ बीमार

कोरिया। बैकुंठपुर जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लैब बनाया जा रहा था। लैब का काम महीनों बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग का दावा था कि लैब का काम पूरा होते ही 114 तरह के टेस्ट यहां होने लगेंगे। तय समय पर लैब का काम पूरा नहीं होन से गरीब और बुजुर्ग मरीजों को निजी लैब में टेस्ट के लिए जाना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में अभी सिर्फ 70 बीमारियों के टेस्ट ही हो रहे हैं। मरीजों की शिकायत है कि लैब को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया। फर्स्ट फ्लोर पर हमेशा पानी जमा होता है जिसे हादसे की संभावना बनी रहती है। जिला अस्पताल के सीएएचओ आरएस सेंगर का कहना है कि फिनिशिंग का कुछ काम अटका पड़ा है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लैब का निर्माण सीजीएमएससी कर रही है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ठेकेदार ने वादा किया है कि वो दिसंबर तक काम पूरा कर लैब हैंडओव्हर कर देगा। ठेकेदार की शिकायत थी कि जब काम का टेंडर दिया गया था तब लागत कम थी।

गोंडवाना 6 से 9 व छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 6 से 10 तक रद्द

बिलासपुर। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मण्डल के भोपाल-इटारसी रेल खंड पर बुदनी-बरखेड़ा (घाट सेक्शन) के मध्य तीसरी लाइन चालू करने के सम्बंध में बुदनी, मिडघाट, चौका एवं बरखेड़ा स्टेशनों पर प्री नॉन/नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। जिसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली गोंडवाना और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। 6 एवं 7 दिसम्बर को निज़ामुद्दीन से चलने वाली 12410 निज़ामुद्दीन-रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 8 एवं 09 दिसम्बर को रायगढ़ से चलने वाली 12409 रायगढ़- निज़ामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 6, 7 एवं 8 दिसम्बर को कोरबा से चलने वाली 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 8, 09 एवं 10 दिसम्बर को अमृतसर से चलने वाली 18238 अमृतसर- बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 6 से 8 दिसम्बर तक बिलासपुर से चलने वाली 08210 बिलासपुर-कोरबा पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

चोरी के 13 मामलों का खुलासा, जेवर बरामद

भिलाई नगर। एसएसपी दुर्ग ने चोरी के 13 मामलों का खुलासा किया है। इन 13 मामलों में 2 गैंग के 7 आरोपी और 3 खरीददार को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 64 लाख 75 हजार का सामान और जेवरात जब्त हुआ है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी सकलैन, सयान, फरहान, विशाल सिंह, आकाश, गोल्डी पूर्व में भी नकबजनी के मामलों में पकड़े गए हैं। पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने बताया कि आरोपी रेसिंग बाईक में सवार होकर शहर में घूम-घूम कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। एसीसीयू एवं थाना जामुल, पुरानी भिलाई, सुपेला, मोहन नगर की टीम ने संयुक्त रूप से आरोपियों को पकड़ा है। शहर में हुई विभिन्न चोरियों के घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर टीम ने घटना स्थल एवं उसके आस-पास के आवागमन के मार्गों में लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया। फुटेज के आधार पर जेल से रिहा हुए पूर्व के संदिग्धों से पूछताछ कर एवं होटल लॉज से संदिग्धों के फुटेज दिखाकर आरोपियों की पतासाजी के प्रयास किए जा रहे थे।

एक दिसम्बर तक 7782 डाकमत पत्र प्राप्त

दुर्ग। विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत

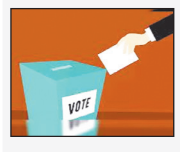

01 दिसम्बर 2023 तक कुल 7782 डाकमत पत्र प्राप्त हुए है। जिला निर्वाचन कार्यालय से अधिकृत नोडल अधिकारी डाक मतपत्र अपर कलेक्टर श्री गोकुल रावटे से प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 62 पाटन में डाकमत पत्र 1094, विधानसभा क्षेत्र क्र. 63 दुर्ग ग्रामीण में डाकमत पत्र 1413, विधानसभा क्षेत्र क्र. 64 दुर्ग शहर में डाकमत पत्र 2260, विधानसभा क्षेत्र क्र. 65 भिलाई नगर में डाकमत पत्र 951, विधानसभा क्षेत्र क्र. 66 वैशाली नगर में डाकमत पत्र 1132 एवं विधानसभा क्षेत्र क्र. 67 अहिवारा में 932 डाकमत पत्र प्राप्त हुए है। इनमें निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाताओं हेतु सुविधा केन्द्र से विशेष संवाहक द्वारा प्राप्त डाकमत पत्रों की संख्या 6846, डाक द्वारा प्राप्त डाकमत पत्रों की संख्या 476 और विशेष गठित मतदान दल द्वारा दिव्यांग, 80 प्लस एवं कोविड प्लस के डाकमत पत्र 460 शामिल है।

सिंचाई विभाग के कार्यपालन अभियंता की संदिग्ध मौत

कोरबा। सिंचाई विभाग के कार्य पालन अभियंता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक के शरीर में चोट के निशान मिलने की बात कही जा रही हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सीएसपी सहित अन्य अधिकारी जांच पड़ताल में जुट गए। मानिकपुर पुलिस चौकी अंतर्गत घंटाघर के समीप पावर हाइट्स के मून ब्लॉक के आवास क्रमांक 304 में सिंचाई विभाग के कार्यपालन अभियंता राजेश धवनकर निवास करते थे। उन्हें गुरुवार की देर शाम इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने परीक्षण उपरांत धवनकर को मृत घोषित कर दिया। मामला संदिग्ध होने के कारण डॉक्टर ने तत्काल अस्पताल पुलिस को मेमो भेज दिया। जैसे ही सिंचाई विभाग के अफसर के मौत की खबर मिली पुलिस हरकत में आ गई। नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का, नगर कोतवाल रूपक शर्मा व सिविल लाइन प्रभारी मृत्युंजय पांडे सहित अन्य अधिकारी व जवान मौके पर जा पहुंचे।

धान पासिंग के नाम पर किसानों से हो रही अवैध वसूली

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड के धान खरीदी केंद्र निमधा में ग्रेडर द्वारा धान पासिंग के लिए किसानों से अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत है कि कृषि विभाग का कर्मचारी शेख इरफान द्वारा धान खरीदी केंद्र में किसानों से धान पासिंग करने के लिए हजारों रुपए वसूल लिए गए हैं। किसानों का आरोप है कि उक्त ग्रेडर अवैध वसूली करते हुए कहता है कि कलेक्टर और एसडीएम व उच्च अधिकारियों को भी पैसा देना है।

दूबर पर दो आषाढ़ की कहावत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के किसानों पर बिल्कुल ठीक बैठती है। हाड़-तोड़ परिश्रम एवं पूंजी लगाने के बाद हुई धान की फसल को बेचने में किसानों को अपना आर्थिक शोषण करना पड़ रहा है, यह कारनामा जिले के धान खरीदी केंद्रों में खुलेआम चल रहा है। कठिन

परिश्रम के बाद जब अपने खून पसीने की कमाई बेचने किसान धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहा है, तो वहां धान पासिंग करने वाले कृषि अधिकारी जिन्हें ग्रेडर कहा जाता है, वह किसानों से धान पासिंग करने के एवज में अवैध वसूली कर रहे हैं।

पैसा नहीं देने के कारण कहीं ग्रेडर नाराज ना हो जाए और उनका धान खरीदी के लिए निरस्त न कर दे इस डर से किसान भी दुखी मन से ही शोषण का शिकार हो रहे हैं, ऐसे में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में किसानों की ऐसी स्थिति हो गई है कि आखिर यह किसान जाए तो जाए कहां। ग्रेडर द्वारा अवैध वसूली किए जाने का ऐसा ही एक मामला जिले के निमधा स्थित धान खरीदी केंद्र में प्रकाश में आया है जहां धान खरीदी केंद्र में नियुक्त कृषि कर्मचारी जो ग्रेडर है के द्वारा किसानों से हजारों रुपए की वसूली की जा रही है। शोषित किसानों ने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि ग्रेडर शेख इरफान द्वारा उनसे धान पासिंग करने के लिए पैसे की वसूली की गई है किसी किसान से 6000 किसी किसान से 1500 रुपये की वसूली सिर्फ इसलिए की गई कि यदि वह पैसा नहीं देंगे तो उनका धान खरीदी के लिए पास नहीं किया जाएगा। किसानों ने बताया कि उक्त ग्रेडर शेख इरफान द्वारा किसानों से यह भी कहा जा रहा है की जिले की कलेक्टर और एसडीएम व उच्च अधिकारियों को भी इस पैसे को देना पड़ता है।

बता दें कि जब से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी की कीमत बढ़ाई गई है तब से सरकारी तंत्र से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों की टेढ़ी निगाह किसानों की गाढ़ी कमाई पर है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के परिणाम तीन दिसंबर को आने हैं तथा चुनाव परिणाम के बाद किसानों के धान खरीदी का क्रय मूल्य और अधिक होने की संभावना है। ऐसे में धान खरीदी से जुड़े अधिकारी कर्मचारी धान बेचने आए किसानों को मोटा मुर्गा की निगाह से देख रहे हैं। तथा उनकी नजर किसान को होने वाली संभावित कमाई पर है। ऐसे में अब जरूरी है कि धान खरीदी चलने तक जिला प्रशासन ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करें जो धान खरीदी में किसानों को शोषण से बचा सके।

हाथी ने महिला को पटक-पटककर उतारा मौत के घाट, दहशत में ग्रामीण

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ वन परीक्षेत्र में हाथी ने एक महिला को पटक-पटककर मार डाला। इस घटना से ग्रामीण दहशत में हैं। घटना के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट पर है और लोगों को हाथियों से बचाव को लेकर आगाह कर रहे हैं। शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत पतरा टोली में सुबह के समय 11 हाथियों का दल ने जमकर उत्पात मचाया है। वहीं हाथियों के आने की जानकारी लगते ही विधवा महिला बसंती देवी अपनी जान बचाते हुए भागने लगी तभी हाथियों के झुंड से इसका सामना हो गया और हाथियों ने पटक-पटक कर महिला की जान ले ली। हाथियों के हमले से महिला के शव दो टुकड़ों में बट गया। वहीं जैसे ही इसकी जानकारी गांव के लोगों को लगी तो अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना तत्काल गांव वालों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को गांव से खदेड़ा और मृतिका के शव को पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।वहीं मृतिका के परिजनों को वन विभाग ने तत्काल सहायता राशि दी। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाथी क्षेत्र से अचानक शंकरगढ़ वन परीक्षेत्र में आए हुए हैं। आने की जानकारी लगते ही हमारे द्वारा गांव में मुनादी करा दी गई थी और गांव के लोगों को अलर्ट कर दिया गया था कि गांव के समीप हाथियों का झुंड आया हुआ है, सभी लोग सतर्क रहें। लेकिन अचानक से हाथियों के सामना होने से या घटना घटी है। एक हफ्ते में दो लोगों की मौत हाथियों के हमले से हुई है। वन विभाग लगातार लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील कर रहा है।

संक्षिप्त समाचार

तीन को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रायपुर आने की संभावना

रायपुर। उपराष्टपति बनने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ के तीन दिसंबर को रायपुर आने की संभावना है। हालांकि अधिकृत तौर पर अभी उनके आने और कार्यक्रम का प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तीन दिसंबर को उपराष्टपति रायपुर आएंगे और हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ व्याख्यान होगा। बताया जाता है कि राजभवन में वे विश्राम करेंगे।

छाया वर्मा के घर पहुंचे सीएम बघेल शोकाकुल परिवार को बंधाया ढांढस

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांग्रेस नेत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा के घर किरना (सिलयारी) पहुंचे। जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। दरअसल, गुरुवार को छाया वर्मा के पति डॉ। दया वर्मा का निधन हो गया। उन्होंने अंबडेकर अस्पताल में अंतिम सांसें ली। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। डॉ. दया वर्मा शासकीय चिकित्सक थे। उनके पति डॉ। दया वर्मा सिलयारी उपस्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय तक पदस्थ रहे। सिलयारी के समीप ही उनका गांव किरना है, जहां बजरंग पावर प्लांट है। छाया वर्मा के पति के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पूर्व राज्यसभा सांसद, कांग्रेस नेत्री छाया वर्मा के पति डॉ। दया वर्मा का दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं परिवारजनों को संबल प्रदान करे। इस दु:ख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं।

विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए स्वागत-कक्ष 4 से 8 तक रहेगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की षष्ठम विधान सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों के लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा भवन में 4 से 8 दिसम्बर तक स्वागत-कक्ष की व्यवस्था की गयी है। इस स्वागत कक्ष में षष्ठम विधान सभा के लिए नव-निर्वाचित सदस्यों के औपचारिक स्वागत के साथ ही उन्हें विधान सभा संबंधी कार्यां हेतु आवश्यक समस्त प्रपत्रों की पूर्ति एवं विधान सभा भवन स्थित समस्त शाखाओं द्वारा सम्पादित कार्यो तथा सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की सम्पूर्ण जानकारी दी जाऐगी। नव-निर्वाचित सदस्यों से अपेक्षा रहेगी कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निर्वाचन प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लावें। सदस्यों की सुविधा हेतु उक्त समस्त प्रपत्र विधान सभा की वेबसाईट में भी उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें डाउनलोड कर, अपेक्षित जानकारी की पूर्ति कर सदस्य विधान सभा सचिवालय में आकर जमा कर सकते हैं।

खोडियार स्वीट्स के भीतर मिला गन्दगी, 10000 जुर्माना

रायपुर। गन्दगी से सम्बंधित जनशिकायत मिलने पर भनपुरी मुख्य मार्ग में खोडियार स्वीट्स दुकान के भीतर सफाई व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण किया। सम्बंधित दुकान के भीतर गन्दगी मिलने पर प्राप्त जनशिकायत स्थल पर सही पायी गयी। नगर निगम जोन 1 जोन कमिश्नर के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी ने स्थल पर सम्बंधित दुकान के संचालक को भविष्य के लिये कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए तत्काल 10000 रूपये का जुर्माना किया। प्राप्त जनशिकायत का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया गया।

मिया चौंग चक्रवात के कारण 5 व 6 को सूबे में हो सकती है बारिश

रायपुर। बंगाल की खाड़ी में आये तूफान मिया चौंग चक्रवात के कारण छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में 5 व 6 दिसंबर को हल्की से भारी वर्षा की संभावना है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वाविद्यालय ने किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कटी हुई धान को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। जिन खेतों में हाल ही में रबी की बोनी की गई है उन खेतों में पानी का जमाव न होने दें, जल निकास की उचित व्यवस्था करें। अन्यथा अंकुरित बीज व बीज के सडने की समस्या हो सकती है।

मुख्यमंत्री पद पर फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा: टीएस सिंहदेव

रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री पद पर फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा और सभी को स्वीकार्य होगा। 2.5 साल के मुख्यमंत्री फॉर्मूले पर अनुभव साझा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, पिछले पांच साल में ढाई-ढाई साल को लेकर हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा। हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आलाकमान जो निर्णय करेगा वही अंतिम होगा। हम अटकलें नहीं चाहते, क्योंकि इससे रिश्तों में भी तनाव पैदा होता है। इसलिए हमने इसे आलाकमान पर छोड़ने का फैसला किया है। सिंहदेव ने कहा पार्टी जो काम देगी, जो कहेगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। सिंहदेव ने कहा कि पार्टी अगर एक दिन के भी जिम्मेदारी देगी तो भी शिकवा नहीं होगा।

टीएस सिंह देव ने यह भी कहा कि सीट शेयर में वास्तविक वोट शेयर का पता नहीं चलता। जहां तक आरोपों की बात है तो गंदी राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि महादेव ऐप में भी आप देख सकते हैं कि चुनाव से पहले कहा गया था कि 508 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। मतदाता परिपक्व हो गए हैं...लोग इसे राजनीतिक मानते हैं...इसलिए इसका असर नहीं हुआ है। एग्जिट पोल के अनुमानों पर देव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सबसे पुरानी पार्टी राज्य में सत्ता बरकरार रखेगी।

इससे पहले इस साल जून में, देव, जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे, को राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। जब कांग्रेस 2018 में सत्ता में आई, तो देव मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन भूपेश बघेल ने रेस में बाजी मार ली। देव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। दोनों नेताओं के बीच सत्ता को लेकर खींचतान की खबरें आई थीं।

2018 के नतीजों में बीजेपी को मिली करारी हार पर सिंहदेव ने आश्चर्य जताया। सिंहदेव ने कहा कि करीब 80 फीसदी मतदान दो हिस्सों में बंटता है, जिसमें से करीब 30 फीसदी वोट बीजेपी को मिलते हैं और 30 फीसदी हमें। डिप्टी सीएम ने कहा कि हार और जीत का मार्जिन सिर्फ दस पर्सेंट वोटों से इधर उधर होता है। 2018 में जो नतीजे आए और बीजेपी की हार हुई आश्चर्यजनक थी।

एग्जिट पोल के अनुमान

गुरुवार को आए एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की गई है। हालांकि, कांग्रेस को राज्य में बढ़त है। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया पोल में कांग्रेस को 90 में से 40-50 सीटें और बीजेपी को 36-46 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एबीपी सी-वोटर ने कांग्रेस को 41-53 सीटें और बीजेपी को 36-48 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। रिपब्लिक टीवी के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 44-52 सीटें, बीजेपी को 34-42 सीटें दी गईं; इंडिया टीवी-सीएनएक्स पोल में कांग्रेस को 46-56 सीटें और बीजेपी को 30-40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है।

कोई भी ऑपरेशन आ जाए, वह काम नहीं करने वाला : विकास उपाध्याय

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के एग्जिट पोल आने के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच ऑपरेशन लोटस पर रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी ऑपरेशन आ जाए, वह काम करने वाला नहीं है। जनता ने जहां मुहर लगा दी है, सरकार उनकी ही बनेगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के दिल्ली रवानगी चर्चाओं पर विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। मगर विपक्षी पार्टी के लोग ऐसी बातें कर सकते है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत से एक परिवार के रूप में चुनाव लड़ा है। सभी अपने-अपने साथी और कार्यकर्ताओं के साथ है। लगातार सबकी बातचीत हो रही है, सभी को 3 दिसंबर के परिणामों का इंतजार है। 3 दिसंबर को मतगणना होगा। मतगणना से पहले विधायक विकास उपाध्याय राजीव लोचन मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करेंगे और कांग्रेस की जीत की कामना करेंगे। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर विकास उपाध्याय ने कहा कांग्रेस ने 15 साल तक सड़क और सदन की लड़ाई लड़कर सरकार बनाई है। हम लोग लाठियां खाई, खून बहाया और जेल भी गए। चाहे कोई भी ऑपरेशन आ जाए, वह काम करने वाला नहीं है। जनता ने जहां मुहर लगा दी है, सरकार उनकी ही बनेगी।

रमन सिंह बोलें-52 से 55 सीटों के साथ बनाएंगे सरकार, साव बोले- कांग्रेस ने किया ठगने का काम

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना तीन दिसंबर को होगी, लेकिन सभी दलों के नेता अपनी-अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद राज्य के पूर्व सीएम रमन सिंह समेत भाजपा के कई नेताओं ने पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है। वहीं एग्जिट पोल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि एग्जिट पोल का आकार सीमित होता है। भारतीय जनता पार्टी का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। मैं डेढ़ साल से पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं, एक-एक विधानसभा में जाकर जनता से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया उस आधार पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में तीन दिसंबर को जब मतगणना होगी तब छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा।

छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया और छत्तीसगढ़ को अपराध और नशे का गढ़ बना दिया।

वहीं पूर्व सीएम ने दावा करते हुआ की भाजपा 52 से 55 सीटों के साथ राज्य में सरकार बनाने जा रही है। रमन सिंह ने कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने यह तो स्पष्ट

कर दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीटें तेजी से बढ़ी हैं और कांग्रेस की सीटें तेजी से कम हुई हैं।

पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि किसान, महिला, युवा समेत प्रदेश के हर वर्ग ने भाजपा के समर्थन में जिस उत्साह और कांग्रेस के प्रति जिस आक्रोश के साथ मतदान किया है वह @BJPyCGState को 48 सीटों पर नहीं रुकने देगी और हम 52-55 सीटों के साथ प्रदेश में सरकार बनाएंगे।

प्रदेश में बनेगी बीजेपी की सरकार, भाजपा का दावा

भाजपा अध्यक्ष साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी भ्रष्टाचार, लूट, नशा और धोखाधड़ी का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के जनता कांग्रेस के पिछले 5 साल के काम से निराश है। कांग्रेस ने प्रदेश के सभी वर्ग के लोगों को धोखा दिया है।

राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी छत्तीसगढ़ एक्जिट पोल से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा पहले से है वहां दोबारा सरकार बन रही है। जहां भाजपा सरकार में नहीं है वहां भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। सरोज पांडे ने दावा किया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है।

वहीं एग्जिट पोल पर भाजपा की ओर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने अपने बयान में कहा कि हमारा आकलन है और स्पष्ट मत है की छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार बनेगी। यह जो सर्वे है, वह मात्र आकलन है। इसलिए प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। जनता एक स्नेह भाजपा को प्राप्त होगा और स्पष्ट बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा।

एबीपी सी-वोटर की भविष्यवाणियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 41-53 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 36-48 सीटें और अन्य को 0-4 सीटें मिलने की संभावना है।

एग्जिट पोल के नतीजों से छत्तीसगढ़ कांग्रेस गदगद

गुलाब कमरो ने किया 75 पार का दावा

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। 30 नवंबर की शाम को आए ज्यादातर एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई गई। एग्जिट पोल को देखने के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। बीजेपी ने एग्जिट पोल पर कहा है कि एग्जिट पोल के दिखाए गए नतीजे तीन दिसंबर के नतीजों से अलग होंगे। भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो ने कहा कि जनता का फिर से आशीर्वाद हमें मिलेगा। कमरो ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम भूपेश सरकार ने किए उन कामों पर जनता ने मुहर लगाया। मनेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रमेश सिंह ने दावा किया कि एग्जिट पोल में जो सीटें मिली हैं उससे ज्यादा सीटें हम जीतेंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर जो तमाम एग्जिट पोल किए गए, सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। भरतपुर सोनहत और मनेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशियों ने दावा किया है कि हम एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो और रमेश सिंह ने एग्जिट पोल में जीत का श्रेय भूपेश बघेल सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को दिया। गुलाब कमरो का मानना है कि सीएम

ने जो धान पर बोनस और किसान कर्ज माफी का ऐलान किया उसका फायदा कांग्रेस को सीधे तौर पर मिला। रमेश सिंह ने कहा कि सीएम ने जो 36 वादे जनता से किए सरकार बनने के बाद वो पूरे करेंगे। 2018 में भी हमने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा किया।

एग्जिट पोल पर कांग्रेस ने भरोसा तो जताया है साथ ही कहा है कि हम एग्जिट पोल से भी ज्यादा बेहतर नतीजे लाएंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का मानना है कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में अंडर करंट था, उसका फायदा हमें मिलेगा। कांग्रेस ने दावा किया हम 75 पार सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे।

कांग्रेस नेता ने कलेक्टर-एसपी से की भाजपा प्रत्याशी पर कार्रवाई की मांग

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान हो चुके हैं और अब दो दिन बाद यानी 3 दिसंबर को इसके परिणाम आने वाले हैं। इस बीच बलौदाबाजार जिले में राजनीतिक प्रतिद्वंदता का आलम यह है कि कांग्रेस नेता ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

दरअसल, पूरा मामला बलौदाबाजार से भाजपा प्रत्याशी टंकराम वर्मा की ओर से पलारी

थाना में 17 नवंबर को दर्ज कराई गई शिकायत ?से है। भाजपा प्रत्याशी ने शि?कायत में बताया है कि रात लगभग 2 ।30 बजे के आसपास उनके घर में अज्ञात लोगों की ओर से गाली-गलौज और दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया गया। साथ ही उनकी एक कार को ड्राइवर सहित ले गए हैं। वहीं अब कांग्रेस ने कलेक्टर और एसपी को सौंपे ज्ञापन में इस शिकायत को झूठा बताया है।

कांग्रेस नेता ने भाजपा प्रत्याशी के आरोप को झूठा बताते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी की छवि को धूमिल करने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके ड्राइवर ने पर्चे फेंके जाने की बात न्यायालय में स्वीकार की है। इस पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने निर्वाचन अभिकर्ता लखेश साहू से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

वहीं, भाजपा प्रत्याशी टंकराम वर्मा ने कहा कि उनके घर पर तोड़फोड़ हुई थी। पलारी थानेदार स्वयं आये थे और उन्होंने देखा है। तोड़फोड़ और ड्राइवर को गाड़ी सहित ले जाने का दोनों मामला अलग-अलग है। उन्होंने कहा कि न्यायालय की ओर से दिए गए निर्णय की जानकारी उन्हें नहीं है।

इस मामले में एसपी दीपक झा ने कहा कि शिकायत प्राप्त हुई है। जांच चल रही है। इस मामले में जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।

सेमीफाइनल में कांग्रेस 4 राज्यों में सरकार बनाएगी लोकसभा चुनाव में मिलेगा फायदा : दीपक बैज

बस्तर। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 के एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्यप्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुसार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया कि सेमीफाइनल को कांग्रेस को मिली जीत का असर फाइनल यानी लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दूसरे राज्यों के एग्जिट पोल अच्छे हैं। मध्य प्रदेश का माहौल भी कांग्रेस के पक्ष में हैं। तेलंगाना में कांग्रेस लहर है। वहां करीब 80 फीसदी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस चार राज्यों में सरकार बनाएगी। बैज ने कहा कि ये सेमीफाइनल के नतीजे हैं आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा। दीपक बैज ने राजस्थान के एग्जिट पोल पर कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बेहतर काम किया है। इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान बल्कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस जनता के साथ किए हर वादों को पूरा कर रही हैं। दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कई हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया। बैज ने कहा कि चुनाव से पहले ईडी, आईटी के दबाव, पैसों के दुरुपयोग के आरोपों के बाद भी एग्जिट पोल में कांग्रेस को 4 राज्यों में स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। ये कांग्रेस सरकार के काम के कारण ही मुमकिन हो पाया है।

कैट की बैठक में जिला ईकाइयों का पुर्नगठन व विभिन्न विभागों के लिए समिति गठन पर सहमति बनी

रायपुर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि आज कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी की अध्यक्षयता में कैट के प्रदेश कार्यालय कैट एवं युवा पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें जिला ईकाइयों का पुर्नगठन व विभिन्न विभागों के लिए समिति गठन पर सहमति बनी व बताया गया कि 19 दिसम्बर को कैट के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक एवं दीपावली मिलन समारोह का अयोजन किया जायेगा।

कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया की आगामी 19 दिसम्बर को कैट के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक एवं दीपावली मिलन समारोह का अयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम की रूपरेखा की

तैयारी कर सभी पदाधिकारियों को कार्य का आंबटन किया गया। कैट और वैश्विक कंपनी मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एवं फेसबुक द्वारा स्थानीय व्यापारियों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित हाइपर-स्थानीय डिजिटल प्रशिक्षण के साथ व्यवसायों के लिए विकास के अवसरों को उजागर करने के लिए डिजिटलीकरण प्रयासों को अंतिम व्यापारी तक पहुँचाना है। डिजिटल और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना हैं। सायबर क्राइम कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। छोटे व्यापारियों के लिए गुमाशता बनाने हेतु शिविर लगाया जायेगा। एमएसएमई पर कार्यशाला का अयोजन किया जायेगा। तथा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन शिविर लगाया जायेगा। प्रदेश स्तरीय जीएसटी कार्यशाला का आयोजन जायेगा। जिसमें माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, केन्द्रीय वित्त मंत्री, को आंमत्रित किया जायेगा। आने वाले समय में प्रदेश के सभी जिला ईकाइयों का पुर्नगठन एवं विभिन्न विभागों के लिए समिति गठन पर सहमति बनी।

बैठक में कैट एवं युवा टीम के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे अमर पारवानी, जितेन्द्र दोशी, विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, अजय अग्रवाल, अवनीत सिंह, विजय पटेल, कैलाश खेमानी, सुनील धुप्पड, महेन्द्र कुमार बागरोडिया, सूरज उपाध्याय, प्रीतपाल सिंह बग्गा, महेश जेठानी, मोहन वर्ल्यानी, नागेन्द्र कुमार तिवारी, विक्रांत राठौर, परविन्द्रर सिंह, अमीत गुप्ता, मनीष कुमार सोनी, गुरूदीप सिंह आनन्द एवं अमित प्रजापति।

सिम्स के ओएसडी का हाई कोर्ट में कबूलनामा

डॉक्टरों में नहीं है वर्क कल्चर, प्राइवेट प्रैक्टिस पर रहता है ज्यादा ध्यान

बिलासपुर। सिम्स की बदहाली पर स्वत: संज्ञान याचिका पर हाईकोर्ट की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सिम्स के ओएसडी ने माना कि सिम्स के डॉक्टरों में वर्क कल्चर नहीं है। डॉक्टरों का ज्यादा ध्यान प्राइवेट प्रैक्टिस पर रहता है। हाई कोर्ट ने डीन और एमएस को व्यवस्था बनाने में असफल बताते हुए 6 दिसंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है।

बीते दिनों सिम्स की अव्यवस्था को लेकर मीडिया में आ रही खबरों को लेकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संज्ञान लिया था। इसके बाद एक जनहित याचिका के रूप में इस मामले की सुनवाई की जा रही है। पूर्व में हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य शासन के सीनियर आईएएस आर प्रसन्ना को सिम्स के ओएसडी के रूप में काम करते हुए

अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

ओएसडी ने चीफ जस्टिस व जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डीबी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें स्वीकार किया गया है कि सिम्स में वर्क कल्चर पूरी तरह प्रभावित हो गया है। इसे वापस पटरी पर लाने में अभी बहुत समय लगेगा।

हाई कोर्ट ने एडवोकेट सूर्या कंवलकर डांगी, अपूर्व त्रिपाठी और संघर्ष पाण्डेय को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सिम्स में पूरी जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। कोर्ट कमिश्नरों ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में बताया गया कि बहुत से डॉक्टर प्रायवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि इन्हें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस तो मिलता होगा। इस पर बताया गया कि शासन जिला अस्पताल में तो यह देता है, लेकिन सिम्स के एक मेडिकल कालेज होने के कारण यहां का प्रावधान स्पष्ट नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर अपूर्व त्रिपाठी ने बताया कि सिम्स के ठीक सामने ही कई निजी डायग्नोस्टिक सेंटर भी चल रहे हैं। कई जांच सिम्स न होने पर मरीजों को यहां आना पड़ता है।

इंडि गठबंधन का क्या होगा थोड़ा इंतजार कीजिए

नदीम

लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में हिस्सेदारी के मुद्दे पर जब क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ तो कांग्रेस ने उस मोर्चे पर वक्ती तौर पर अपने को 'साइन आउट' कर सारा ध्यान पांच राज्यों के चुनाव पर केंद्रित कर लिया। इसी बात को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में झुंझलाए भी थे- 'कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए हम सब लोग एक हुए थे और काम कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को कोई चिंता है नहीं। अभी सब लगे हैं पांच राज्यों के चुनाव में।' ऐसा करना कांग्रेस की मजबूरी भी थी। इंडिया के अंदर कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुनौती सात राज्यों में इलाकाई दलों से मिल रही है। ये राज्य हैं- यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली, जहां से कुल 269 लोकसभा सीटें आती हैं। इन राज्यों में बीजेपी के विरोध में राजनीति करने वाले जो दल हैं, वे कांग्रेस से किसी भी सूरत में कम नहीं हैं। इनमें से यूपी, बिहार, बंगाल और तमिलनाडु में कांग्रेस खुद में कोई ताकत नहीं है। यूपी में गैर-बीजेपी राजनीति सपा-बसपा के इर्द-गिर्द घूमती है। बंगाल में टीएमसी ने वामदलों और कांग्रेस दोनों को नेपथ्य में ढकेल रखा है। बिहार में भी कांग्रेस आरजेडी-जेडीयू की बैसाखी पर ही है। तमिलनाडु में डीएमके के बगैर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। इसके अलावा 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में भी एनसीपी और शिवसेना का दबदबा कांग्रेस से कहीं ज्यादा दिखता है। पंजाब और दिल्ली में जहां कभी गैर-बीजेपी दल के रूप में कांग्रेस जानी जाती थी, वह जगह आम आदमी पार्टी ने ले ली है। राजनीति को 'पावर गेम' कहा ही जाता है। ऐसे में ये दल अपने अपने राज्यों में इंडिया की 'ड्राइविंग सीट' पर खुद ही रहना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि सीटों के बंटवारे में कांग्रेस की कोई दखलंदाजी हो। अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि कोई भी गठबंधन हो, सपा उसमें सीटें मांगने वाली नहीं बल्कि सीटें बांटने वाली पार्टी होगी। ऐसा ही रुख ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक का है। अलग-अलग मौकों पर इन पार्टियों के नेता यह कह चुके हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीट देने का मतलब बीजेपी के लिए ज्यादा स्पेस उपलब्ध कराने का जोखिम उठाना है। इस सिलसिले में 2020 बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया जा रहा है कि जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन से 70 सीटें छुड़वा लीं थीं, लेकिन उनमें से महज 19 ही जीत पाईं थी। नतीजों के बाद जब महागठबंधन महज 12 सीटों के अंतर से सरकार नहीं बना पाया, तब आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया था कि 'कांग्रेस के ज्यादा सीटें लेने से महागठबंधन की हार हुई। कांग्रेस ने 70 सीटें ले लीं, लेकिन वह 70 रैलियां भी नहीं कर पाई। अगर ये सीटें आरजेडी के पास होतीं तो महागठबंधन बहुमत हासिल कर लेता।' इसी प्रेशर की वजह से कांग्रेस नेताओं को लगा कि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर फौरी तकरार से बचा जाए और इसके लिए पांच राज्यों के नतीजों का इंतजार किया जाए। ये वैसे राज्य हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। दो राज्यों में तो उसकी सरकार भी है। कांग्रेस को लगता है कि इन पांच राज्यों में अगर वह बेहतर प्रदर्शन कर पाई तो यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली में उस पर जो दबाव बन रहा है, उसे वह टाल सकती है। रिजल्ट अच्छा रहा तो वह इन राज्यों में इंडिया में शामिल दलों को यह दिखा पाएगी कि उसे कमतर आंकने की भूल न की जाए। इसके बाद कांग्रेस इन राज्यों में भी अधिक सीटों का दावा कर सकती है। कांग्रेस के रणनीतिकार इन राज्यों से सिर्फ सीट बंटवारे तक अपनी चुनौती नहीं मानते। उन्हें लगता है कि इंडिया में शामिल दलों के हिस्से में अगर ज्यादा सीटें गईं तो नतीजों के बाद इन दलों के पास मोलभाव की ताकत ज्यादा होगी। उन्हें अपने पाले में बनाए रखने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी होगी। वहीं, अगर पांच राज्यों के नतीजे कांग्रेस की उम्मीद के अनुरूप नहीं आते हैं तो उसके लिए इंडिया के भीतर चुनौती और बढ़ेगी।

जनमन और एक्जिट पोल

संजय तिवारी

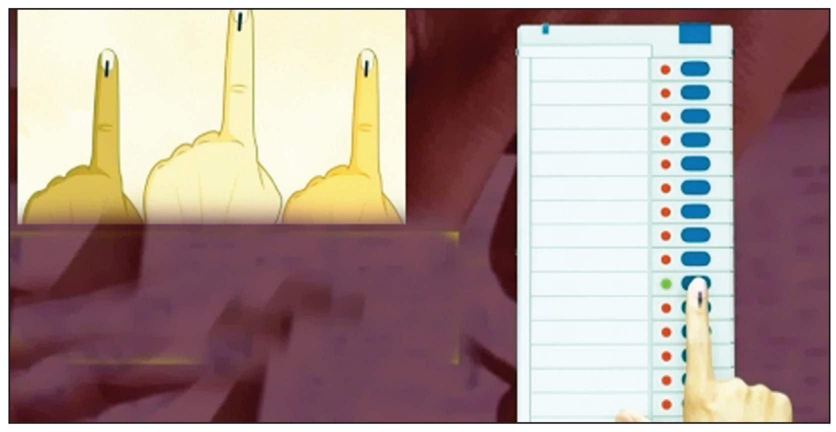

एक बार फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ और तेलंगाना में हुए मतदान के बाद हुए एक्जिट पोल को लेकर माहौल गर्म है तब सवाल यह भी उठता है कि उनके सही गलत साबित होने का प्रतिशत क्या है? बहुत इतिहास में न भी जाएं तो 2014 का लोकसभा चुनाव इसका बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है। उस समय जितने भी एक्जिट पोल थे वो सब एनडीए को बहुमत या बहुमत के आसपास पहुंचता तो बता रहे थे लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अकेले भाजपा 282 सीटें हासिल कर लेगी।

मतदान के दौरान लोगों का मत जानना और मतगणना से पहले उसे सबको बता देने का नाम एक्जिट पोल है। इस एक्जिट पोल की शुरुआत टीवी न्यूज की देन है। 1967 में अमेरिका और जर्मनी में टीवी चैनलों के लिए इस पद्धति का प्रयोग करके यह जानने की कोशिश की गयी कि स्थानीय चुनावों में जनता किसे चुनने जा रही है। क्रमश- यह गति आगे बढ़ी और दुनियाभर में जैसे जैसे टीवी न्यूज का प्रसार हुआ एक्जिट पोल का भी विस्तार होता गया।

भारत में एक्जिट पोल का इतिहास काफी पुराना है। 1957 में पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपनियिन द्वारा जनमन जानने का प्रयास किया गया था। इसके बाद दूरदर्शन की शुरुआत और प्रसार के दौर में भी जनमन जानने का काम जारी रहा। लेकिन 24ङ्क7 न्यूज चैनलों के आगमन के साथ इसका भारतीय चुनावों में व्यापक विस्तार हो गया।

शुरुआत में यह इतना अधिक बेलगाम था कि मतदान के विभिन्न चरणों के दौरान ही सर्वेक्षण करके बताता रहता था कि किस चरण में किस पार्टी को लीड मिल रही है। जब चुनाव आयोग को यह महसूस हुआ कि इससे तो पूरी वोटिंग प्रभावित हो रही है तब मतदान के दौरान एक्जिट पोल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया। अब टीवी चैनल और सर्वे एजंसियां मिलकर मतदाता का मूड तो जान सकती हैं लेकिन उसे चैनल पर प्रसारित नहीं कर सकतीं। इसके लिए उन्हें आखिरी दिन के मतदान का इंतजार करना होता है ताकि उनके प्रसारण से मतदाता के मूड पर कोई प्रभाव न पड़े।

टीवी चैनलों के लिए यह एक फायदे का सौदा होता है क्योंकि इस दौरान दर्शकों की संख्या बढ़ती है और उनके एयरटाइम का रेट भी। जो सर्वेक्षण एजेंसियां होती हैं उनके लिए भी यह एक नियमित काम बन गया है। हर लोकसभा या विधानसभा चुनावों से पहले वो व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण करने का दावा करके अपने लिए व्यावसायिक अवसर पैदा करती हैं। फिर इन सर्वेक्षणों का विश्लेषण करनेवाले सेफोलॉजिस्ट भी होते हैं जो दावा करते हैं कि वही हैं जो जनता का मूड समझ सकने में कामयाब हैं। इसलिए उनकी बात पर भरोसा किया जाना चाहिए।

लेकिन यह सब तब तक काम का है, जब तक वास्तविक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते। जैसे ही वास्तविक चुनाव परिणाम घोषित होते हैं, किसी को याद नहीं रहता कि किस एक्जिट पोल ने क्या दावा किया था। मतगणना से पहले जिस प्रक्रिया पर घण्टों घण्टों टीवी पर बहस होती है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती हैं, चुनाव परिणाम सामने आते ही उस एक्जिट पोल की किसी को याद भी नहीं आती।

आज जब एक बार फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ और तेलंगाना में हुए मतदान के बाद हुए एक्जिट पोल को लेकर माहौल गर्म है तब सवाल यह भी उठता है कि उनके सही गलत साबित होने का प्रतिशत क्या है? बहुत इतिहास में न भी जाएं तो 2014 का लोकसभा चुनाव इसका बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है। उस समय जितने भी एक्जिट पोल थे वो सब एनडीए को बहुमत या बहुमत के आसपास पहुंचता तो बता रहे थे लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अकेले बीजेपी 282 सीटें हासिल कर लेगी। उस समय सिर्फ एक नयी नवेली एजेंसी चाणक्या ने दावा किया था कि एनडीए को 340 सीटें मिल सकती हैं। जब चुनाव परिणाम आये और एनडीए को 336 सीटें मिलीं तो रातों रात टुडेज चाणक्या की चर्चा चारों ओर हो गयी।

इसलिए तब से लेकर अब तक जब भी कहीं चुनाव होते हैं तब टुडेज चाणक्या के अनुमानों पर जरूर नजर रखी जाती है। मसलन इस बार भी चाणक्या और एक्सिस ने ही सबसे अधिक उलटफेर भरा अनुमान लगाया है। अब तक के अनुमान के उलट टुडेज चाणक्या ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी तो तेलंगाना, छत्तीसगढ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा और राजस्थान में कांग्रेस की वापसी का अनुमान पूर्व में किये गये सभी राजनीतिक आकलनों को ध्वस्त करता है। तेलंगाना में कांग्रेस कोई चमत्कार कर सकती है इसका अनुमान तो पहले भी लगाया ही जा रहा है।

टीवीटुडे-एक्सिस एक्जिट पोल ने भी मध्य प्रदेश में भाजपा की वापसी का अनुमान लगाया है जबकि बाकी सर्वे एजेंसियां कमोबेश राजस्थान में भाजपा तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगा रही हैं। अब तक का एक्जिट पोल का इतिहास देखें तो सटीक आकलन की बजाय तुक्का ही साबित हुए हैं। कई बार ये नतीजों के आसपास पहुंचते हुए दिखते हैं तो कई बार बुरी तरह ध्वस्त नजर आते हैं। वह टुडेज चाणक्या भी कई बार सटीक आकलन नहीं कर पाया है। 2014 में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टुडेज चाणक्या ने भाजपा द्वारा 152 सीट जीतने का दावा किया था लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने इसके लिए माफी भी मांगी थी।

असल में सर्वे कंपनियां कई तरीकों से जनमन को भांपने की कोशिश करती है। इसका सबसे सटीक तरीका मतदान करके बाहर आ रहे लोगों का मन जानना है। इसके अलावा पिछले वोटिंग पैटर्न को भी आधार बनाया जाता है। दलों के गठबंधन की गणना की जाती है। जाति धर्म और वर्ग के आधार पर मतदान को जांचा परखा जाता है। इन सबमें सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है सर्वेयर द्वारा वोटरों से की गयी बातचीत। उसकी बातचीत के आधार पर सर्वे एजेंसियों का सारा दारोमदार रहता है। इसलिए सर्वे सैम्पल की साइज को बहुत अधिक महत्व मिलता है। यानी जितनी ज्यादा संख्या में लोगों से बातचीत उतना अधिक सटीक आकलन होने का अनुमान लगाया जाता है।

लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वोटिंग करनेवाला वोटर सर्वेयर को सही जानकारी देता है? आज जब पार्टियों के घोषित समर्थक या मतदाता मुखर होकर नजर आने लगे हैं तब भी भारत में सामान्य मतदाता ने किसे वोट किया है इसे गुप्त ही रखता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में वो कभी किसी अनजान व्यक्ति को यह बताने से बचता है कि उसने किसे वोट किया है। बतायेगा भी तो सही बता देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा करने के पीछे उसका अपना समाजशास्त्र होता है। वह जिस भी समाज में रहता है वहां राजनीतिक गोलबंदी से बचना चाहता है इसलिए किसे वोट दिया है इसको आमतौर पर गुप्त ही रखता है। आखिरकार उसके घर जो भी वोट मांगने आता है, वह किसी को ना भी तो नहीं करता है, फिर यह कैसे बता देगा कि किसे वोट दिया और किसे नहीं दिया?

यही कारण है कि भारत में एक्जिट पोल अनुमान से आगे सटीकता तक नहीं जा पाते हैं। हां, टीवी स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट हों या सर्वे एजेंसियों के कर्मचारी। उनके लिए यह एक व्यावसायिक संभावनाओं से भरा एक काम जरूर होता है जिससे टीवी चैनल अपने लिए बिजनेस पैदा करते हैं। इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं है इसलिए रस्मी तौर पर हर चुनाव परिणाम से पहले एक्जिट पोल अपनी जगह बनाये हुए हैं। लेकिन यह कहना कि जनमन को समझने का सबसे सटीक फार्मूला एक्जिट पोल करनेवालों के पास है, उचित नहीं होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

यागचूडामण्युपनिषद् (भाग-2)

गतांक से आगे...

आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इस प्रकार योग को छः अंगों वाला कहा गया है। दो प्रकार के आसनों का यहाँ वर्णन है, एक सिद्धासन दूसरा पद्मासन अपने शरीर के भीतर जो साधक षट्चक्र, षोडश आधार, त्रिलक्ष्य और पाँच आकाशों को नहीं देख पाता, उसे सिद्धि कहाँ मिल सकती है? शरीर में स्थित षट्चक्रों में आधारचक्र (मूलाधार चक्र) चार दल वाला है, स्वाधिष्ठान चक्र में छः दल हैं। दस दल वाला चक्र नाभि में स्थित है, द्वादशदल का पद्मचक्र हृदय में है, विशुद्धचक्र षोडश दल वाला तथा दो दल का चक्र भ्रूमध्य में (आज्ञाचक्र के रूप में) स्थित है।

सहस्र दल-कमल ब्रह्मरन्ध्र के महापथ में स्थित है। मूलाधार प्रथम चक्र है तथा स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र है। दोनों के बीच में योनि स्थान (कुण्डलिनी) स्थित है। जगत् की उत्पत्ति का कारण होने से उसे कामरूप कहा जाता है। गुदास्थान में चार दल वाला कमल स्थित है, जिसे काम कहा गया है। उसी के बीच सिद्ध पुरुषों के द्वारा वन्दित पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है।

नाभि स्थान में मणि की आकृति वाले मणिपूर चक्र को जानने वाला ही योगी है। तपाये हुए सोने के समान आभा वाला, विद्युत् की तरह प्रकाशमान त्रिकोण युक्त अग्नि मेढ्र में प्रतिष्ठित है। समाधि अवस्था में उस स्थान पर अनन्त विश्वतोमुख (सब ओर प्रकाशित) परमज्योति के दर्शन होते हैं। योगाभ्यास के समय उस अग्निमयी ज्वाला के दर्शन कर लेने पर संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। प्राण का निवास स्वाधिष्ठान चक्र में कहा गया है। प्राण को ही स्व कहते हैं। स्वाधिष्ठान में स्थित होने के कारण उसे %मेढ्र% भी कहते हैं। जिस प्रकार मणि में तागा पिरोया होता है, उसी प्रकार कन्द (नाड़ी समूह) सुषुम्ना से युक्त है।

क्रमशः ...

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस

दीपक कुमार त्यागी

भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाने का इतिहास जानने के लिए हमको मध्यप्रदेश में 2-3 दिसंबर 1984 की भयावह काली रात को भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड के रासायनिक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम के जहरीले रसायन के साथ ही अन्य बहुत सारे जहरीले रसायनों के रिसाव की झकझोर देने वाली घटना को याद अवश्य करना होगा, दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदा भोपाल गैस त्रासदी ने उस समय हजारों लोगों के अनमोल जीवन को लील करके लाखों लोगों के जीवन को नरक बना दिया था, इस भयंकर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की याद व सम्मान में ही देश में हर वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह एक नयी थीम के साथ देश में आम जनमानस के द्वारा रोजमर्रा के जीवन में बरती जाने वाली लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए 2 दिसंबर, 2023 को एकबार फिर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाएगा। हर वर्ष सरकार का प्रयास होता है कि वह आम जनमानस को प्रदूषण के बारे में जागरूक करें और जल, थल, वायु व ध्वनि प्रदूषण आदि को रोकने के उपाय के बारे में बता कर जागरूकता फैलाकर देश में तेजी से बढ़ते हुए प्रदूषण की गति को कम करके जानलेवा प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास करें, लेकिन धरातल पर तेजी से बढ़ते प्रदूषण के हालात देखकर लगता है कि यह दिवस भी अब केवल औपचारिकता मात्र ही बनता जा रहा है, देश में अब भी बड़ी संख्या में लोग प्रदूषण नियंत्रण करने के उपायों से बच रहे हैं।

वैसे भी विचारणीय तथ्य यह है कि देश व दुनिया में जैसे विज्ञान ने नये-नये आविष्कार किये है, उनके दम पर ही लोगों के द्वारा धरा पर आसानी से औद्योगिक विकास तेजी के साथ किया गया है। लेकिन लोगों की अदूरदर्शिता के चलते अव्यवस्थित विकास ने धरा पर आज प्रकृति के विनाश की तर्ज पर विकास की बुलंद इमारत खड़ी कर डाली, जिसके साथ ही धरती पर तरह-तरह का प्रदूषण अब दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ता ही चला जा रहा है। आज आलम यह हो गया है कि दुनिया भर में विकसित, विकासशील व अविकसित तीनों श्रेणी के ही देश बेहद गंभीर हो चुकी प्रदूषण की समस्या से जबरदस्त ढंग से जूझ रहे हैं। भारत में तो छोटे-बड़े शहर तक भी वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाने के चलते गैस चैंबर बनने लगें है, प्रदूषित जहरीली वायु में सांस लेने की मजबूरी के चलते अब तो लोग बीमार व तिल-तिल कर मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात यह है कि फिर भी हमारे देश का सिस्टम व लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं।

बेहद महत्वपूर्ण है जलवायु सम्मेलन

डॉ. वैभव चतुर्वेदी/जैद अहसान खान

दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) में 30 नवंबर से शुरू हो चुके 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (कॉप-28) पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इसमें 195 देश, 2015 के पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पक्षकार, राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों, उन्हें पाने के साधनों और ग्लोबल स्टॉकटेक (जीएसटी) प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में वैश्विक प्रगति के आकलन के लिए बातचीत करेंगे। पेरिस समझौते के तहत यह पहला ग्लोबल स्टॉकटेक है, जो कॉप-28 में पूरा होगा। सरल शब्दों में, ग्लोबल स्टॉकटेक पांच वर्ष तक चलने वाली एक समीक्षा प्रक्रिया है, जो एक तरह का रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है।

यह रिपोर्ट कार्ड दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने की दिशा में सभी देशों की सामूहिक प्रगति कितनी रही है और हम वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम पर सीमित रखने के रास्ते पर हैं या नहीं। कॉप-28 के दौरान होने वाली बातचीत से हमें उम्मीद है कि जीएसटी के नतीजे इन चर्चाओं को प्रेरित करने का काम करेंगे। जलवायु गतिविधियों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने और इस दिशा में जरूरी फैसलों को अगले वर्षों के लिए न टालने के लिए कॉप-28 को चार क्षेत्रों में नतीजे पर पहुंचना होगा।

पहला, सभी देशों को सामूहिक रूप से स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और उनके उत्पादन के लिए जरूरी खनिजों की आपूर्ति शृंखला बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जी20 देशों के दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीतियों का आकलन करने वाली काउंसिल ऑन एनर्जी, इनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीइइडब्ल्यू) की रिपोर्ट बताती है कि इसमें केवल भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने ही कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति शृंखला बनाने का समर्थन करने वाले मिशन इनोवेशन या क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल जैसी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय साझेदारियों के उदाहरणों का उल्लेख किया है।

इसलिए एक वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था बनाने की जरूरत है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और ईंधनों के लिए साझे नवाचारों को सक्षम बनाने के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहना चाहिए। हाल में हुए आइइए क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन में लगभग 50 देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों की विविधतापूर्ण और सतत आपूर्ति की दिशा में प्रगति को तेज करने पर सहमति जतायी है। कॉप-28 को भी महत्वपूर्ण खनिजों की विविधतापूर्ण और सतत आपूर्ति शृंखला बनाने वाले तंत्र की पहचान करनी चाहिए। इस संदर्भ में एक उपाय के रूप में महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच और प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए एक सामान्य वर्गीकरण को स्थापित किया जाए।

दूसरा, ऊर्जा परिवर्तन के लिए जरूरी वित्त की मात्रा पर निर्णय लिया जाना चाहिए। ऊर्जा परिवर्तन को पाने में जलवायु वित्त की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी20 के नयी दिल्ली शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी) के लक्ष्यों को पाने में सहायता करने के लिए 2030 से पहले 5.8-5.9 ट्रिलियन डॉलर जुटाने पर जोर दिया गया है। विकसित देशों की ओर से उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता बहुत कम रही है। उम्मीद है कि विकसित देश वित्त उपलब्ध कराने के इरादे को सामने रखेंगे। एक सफल और समावेशी वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन अपनी नींव में साझेदारी को रखता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बाजार के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी को स्पष्टता से प्रसारित किया जाए, ताकि विकासशील देशों में ऊर्जा परिवर्तन के वित्तपोषण के लिए विकसित दुनिया से निवेश लाया जा सके।

तीसरा, जलवायु वित्त की परिभाषा को स्पष्ट किया जाना चाहिए, ताकि धन के लिए उचित और पर्याप्त स्रोतों को अनुमति देने के साथ वितरण को सुविधाजनक बनाया जा सके। विकसित अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु वित्त के तहत हानि एवं क्षति, जलवायु अनुकूलन और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक कोष में अंतर करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि कॉप-28 में वितरण की एक संरचना, एक मेजबान संस्था (उदाहरण के लिए, विश्व बैंक अस्थायी रूप से हानि और क्षति कोष की देखभाल करने जा रहा है), और पारदर्शी शर्तों के माध्यम से इन अलग-अलग श्रेणियों का निर्धारण कर दिया जायेगा। जैसे-जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं 2024 में प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर के आधार से आगे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स निर्धारित करने के लिए तैयार हो रही हैं, उन्हें इन कोषों में प्राथमिक योगदानकर्ता बनना चाहिए और इन कोषों को विस्तार देने के लिए इनमें बहुपक्षीय विकास बैंकों को शामिल करना चाहिए।

चौथा, विकसित देशों को अपने-अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों को विस्तार देना चाहिए। विकसित देशों को औद्योगिक युग के बाद अपने बेलगाम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण हुए जलवायु परिवर्तन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। सीइइडब्ल्यू के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, वर्तमान में विकसित देश अपने 2030 लक्ष्यों को पाने के रास्ते पर नहीं है और 2030 में ही उनका उत्सर्जन लक्ष्य से लगभग 3.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जायेगा। इसलिए, विकसित देशों को अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाना चाहिए, ताकि वे जलवायु कार्रवाई के लिए रास्ता बना सकें।

इस साल पहला ग्लोबल स्टॉकटेक पूरा होने के कारण कॉप-28 जलवायु लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक प्रगति को सबके सामने रखेगा और सभी देशों को अपनी प्रतिबद्धताओं के बारे में विचार करने का मौका देगा। सभी देशों के सामने यह सवाल होना चाहिए कि क्या हम ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी को 1।5 डिग्री सेल्सियस से कम पर सीमित रख सकते हैं। जी20 अध्यक्षता के साथ भारत पहले ही जलवायु क्षेत्र में अपने नेतृत्व को दुनिया के सामने रख चुका है, जिसने ऊर्जा परिवर्तन को विकास एजेंडे के केंद्र में रखा है। उभरती अर्थव्यवस्थाएं आगे भी विकास करती रह सकें, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें शेष कार्बन बजट में उचित हिस्सेदारी मिले। ऐसे में जलवायु कार्रवाई पर उद्देश्यपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग पाने के लिए तीन टी- विश्वास (ट्रस्ट), पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) और परिवर्तन (ट्रांसफॉर्मेशन) को अपनाना जरूरी है, जो नेट-जीरो विश्व के लिए आगे की राह दिखायेगा।

आज का इतिहास

1956 क्यूबा के नेता फीडल कास्त्रो ने अपने देश को मुक्ति दिलाने के लिए आंदोलन आरंभ किया।

1971 सात अमीरातों के संघ के रूप में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का गठन हुआ।

1975 पाथेट लाओ ने वियनतियाने में शाही सरकार को उखाड़ फेंका, राजा सवंग वत्थना को छोड़ने के लिए मजबूर किया, और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की।

1976 फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने।

1980 अमेरिकी मिशनरी मौर क्लार्क, जीन डोनोवन, इता फोर्ड और डोरोथी काजेल की अल साल्वाडोर में एक सैन्य मौत दस्ते द्वारा हत्या कर दी गई थी।

1988 बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की पहली महिला के तौर पर प्रधानमंत्री पद संभाला।

1988 बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनीं, जो इस्लाम-प्रभुत्व वाले राज्य की सरकार की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थीं।

1993 नासा ने अंतरिक्ष शटल %एन्डेवर% को लॉन्च किया।

2001 लेखांकन उल्लंघनों का खुलासा करने के दो महीने से भी कम समय बाद, टेक्सास स्थित ऊर्जा फर्म एनरॉन ने अध्याय 11 दिवालियापन के लिए दायर किया, शेयरधारक धन में लगभग .11 बिलियन का वाष्पीकरण किया।

2005 गैबॉन और कांगो गणराज्य के वैज्ञानिकों ने इबोलावायरस के लिए पशु जलाशय होने के लिए फलों के चमगादड़ों की तीन प्रजातियों का पता लगाया। यह माना जाता है कि चमगादड़ खाने वाले स्थानीय शिकारियों के कारण वायरस 1976 में पहली बार जानवर से मानव में फैल गया था।

2006 लंदन में पुलिस जांच कर रही है कि क्या अलेक्जेंडर लिट्विनेंको के हत्यारों ने इतालवी सुरक्षा विशेषज्ञ मारियो स्कारामेला को भी जहर देने की कोशिश की थी।

2007 ब्राजील साओ पाउलो में फ्री-टू-एयर डिजिटल टेलीविजन प्रसारण शुरू करता है, लेकिन प्रसारण कंपनियों को एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रारूपों में जून 2016 तक सिग्नल प्रसारित करना होगा।

2008 थाई प्रधानमंत्री सोमचाई वॉंगसवाट ने 2008 राजनीतिक संकट के बाद इस्तीफा दिया।

2009 ब्रिटिश के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने एक कथित ब्लैकमेलर को खोजने में मदद की अपील के बाद विकिपीडिया को इसकी गोपनीयता का उल्लंघन करने की आज्ञा दी।

चुनाव परिणाम के बाद बढ़ेगा राहुल का कद ?

रमेश सर्राफ धमोरा

देश के पांच राज्यो के विधानसभा चुनावो में कांग्रेस ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। कर्नाटक व हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाकर भाजपा को जबरदस्त पटकनी दी थी। तभी से लगने लगा था कि कांग्रेस धीरे-धीरे अपनी स्थिति सुधार रही है। वहीं केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा का पराभव प्रारंभ हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी तो किसी को सपने में भी गुमान नहीं था कि उनकी यात्रा को आमजन का इतना जन समर्थन मिलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कमजोर होती कांग्रेस में एक नई जान फूंकने का काम किया है।

पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव के ट्रेलर के रूप में देखा जा रहा है। इन राज्यों के नतीजे का असर अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात 26 विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितनी बड़ी चुनौती दे पाएगा इसका पता भी इन विधानसभा चुनाव के परिणामों से लग जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा की कुल 679 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में कांग्रेस प्राय सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

हिंदी भाषी बेल्ट माने जाने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की भाजपा से सीधा मुकाबला है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों प्रदेशों में सरकार बनाई थी। मगर भाजपा ने षडयंत्र पूर्वक मध्य प्रदेश की सरकार को गिरकर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अपनी सरकार बना ली थी। अब इन तीनों ही प्रदेशों में एक बार फिर कांग्रेस व भाजपा में सीधा मुकाबला हो रहा है। यहां मतदान हो चुका है। मतदान के प्रारंभिक रुझानों से लगता है कि कांग्रेस मजबूत बनकर उभर रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने पिछले दो वर्षों में बहुत सी जनहितकारी योजनायें शुरू की थीं। जिसका असर इन चुनाव में भी देखने को मिला है। चुनाव के दौरान राजस्थान में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता से सात वायदे किए हैं तथा कहा है कि यदि फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो वह इन वादों को लागू करेगी। यह सभी वायदे आम जन को खासा प्रभावित कर रहे हैं।

राजस्थान में कांग्रेस ने कमजोर स्थिति वाले बहुत से विधायकों का टिकट काट कर नए लोगों को मौका दिया है। जिससे सरकार के प्रति व्याप्त नाराजगी समाप्त हुई है।

राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह से चुनावी चक्रव्यूह की रचना की थी जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता भी उलझ कर रह गए। कई बड़े जाट नेताओं के भाजपा में जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जाट समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर टिकट दिया थां जिसके चलते जाट समाज के मतदाता कांग्रेस से ही जुड़े रहे हैं।

प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी जाट समाज की है जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। इस बार भी जाटों का कांग्रेस से जुड़ाव कांग्रेस के लिए एक नई संजीवनी साबित हो रहा है। हालांकि भाजपा ने सात सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा था। मगर सभी सांसद चुनावी चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आये। उनके चुनाव लड़ने से भाजपा को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। उसके उलट कांग्रेस ने संगठन से जुड़े कई नए लोगों को अवसर देखकर पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार किया है।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भाजपा द्वारा करवाए गए दल-बदल का लाभ मिलता नजर आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में वहां कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। मगर सवा साल बाद ही भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों से दल-बदल करवाकर कमलनाथ सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार बना ली थी। भाजपा ने वहां अपनी जोड़-तोड़ से सरकार तो बना ली थी। मगर कांग्रेस से भाजपा में आए सिंधिया समर्थक विधायकों व भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं का टकराव कभी समाप्त नहीं हो पाया। यहां तक की टिकट वितरण में भी भाजपा दोनों गुटों को एक जगह करने में असफल रही। इसी के चलते बड़ी संख्या में भाजपा के बागी मैदान में उतरकर भाजपा प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनने व उनके शासन में खुले आम भ्रष्टाचार होने के कारण वहां की जनता में सरकार के प्रति भारी नाराजगी व्याप्त थी। जिसका असर चुनाव में होना तय माना जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते पहले व्यापमं घोटाले का दाग लगा था जो धुल भी नहीं पाया था कि पिछले दिनों पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर भी शिवराज सिंह सरकार को खासी बदनामी झेलनी पड़ी थी।

लगातार चार बार मुख्यमंत्री रहने के कारण मध्य प्रदेश के लोगों में शिवराज सिंह चौहान की नकारात्मक छवि बन चुकी है। जिसका खामियाजा वहां भाजपा को उठाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रियों व सांसदों को मैदान में उतार कर शिवराज सरकार के प्रति व्याप्त हो रही नाराजगी को कम करने का प्रयास किया था। मगर ऐसा हो नहीं पाया। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सरकार के कारनामों के कारण हर हाल में भाजपा सरकार को बदलना चाहती है।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के पहले ऐसे नेता हैं जो पांच साल शासन करने के उपरांत भी प्रदेश की जनता में पहले की तरह लोकप्रिय बने हुए हैं। जमीन से जुड़े होने के कारण बघेल को आम आदमी की समस्याओं का पता है। अपने कार्यकाल में उन्होंने आम आदमी के भले से जुड़ी अनेकों योजनाएं जारी कर लोगों में अपनी सरकार के प्रति नकारात्मक भावना पैदा ही नहीं होने दी। जिसका लाभ उनको विधानसभा चुनाव में भी मिलता दिख रहा है। अंतिम वर्ष में उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी टीएस सिंह देव को उपमुख्यमंत्री बनाकर उनकी नाराजगी ही दूर नहीं की बल्कि कांग्रेस संगठन को भी मजबूत करने का काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल से तंग आ चुकी जनता को भूपेश बघेल ने एक नया नेतृत्व देखकर प्रदेश के सभी वर्गों के विकास का वादा किया था। जिस पर उन्होंने खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है और फिर से सरकार बनाने को लेकर पूरी तरह आशान्वित नजर आ रही है।

तेलंगाना में कांग्रेस ने सबसे अधिक मजबूती दिखाई है। 2014 के बाद तेलंगाना में कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गई थी। मगर इस बार बीआरएस पार्टी के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को कड़ी टक्कर दे रही है। वहां तो स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि भाजपा व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पार्टी में गुप्त समझौता हुआ बताते हैं। जिसके चलते भाजपा कांग्रेस को हराने के लिए अंदरखाने बीआरएस को चुनाव जितवाने का प्रयास कर रही है। इसी के चलते विधानसभा चुनाव प्रचार में भाजपा की तरफ से पहले जैसी आक्रामकता नजर नहीं आयी। मिजोरम में कांग्रेस पूरी ताकत से सत्ता में आने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस नेताओं के चुनाव प्रचार से लगता है कि वहां कांग्रेस अपनी खोई जमीन को फिर से पा लेगी।

पांच राज्यों के एग्जिट पोल ने बढ़ाई सियासी दलों की धड़कनें

निर्मल कांत

पांच राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तेलंगाना में गुरुवार को वोटिंग खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने लगे हैं। तीन दिसंबर को पांचों राज्यों के चुनावों के लिए मतगणना और 2024 के आम चुनाव से पहले इन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नतीजों से पहले सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल ने सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इनमें अलग-अलग भविष्यवाणियां की गई हैं। इन पर सियासी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग है। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा, हम सभी एग्जिट पोल और हमारी पार्टी का लोकल फीडबैक के बाद ही कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। इसके पहले टिप्पणी करना ठीक नहीं है। एग्जिट पोल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अभी 6-7 सर्वे हुए हैं और किसी के भी आंकड़े एक समान नहीं है। हमने 75 पार का लक्ष्य रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, एग्जिट पोल के आंकड़ों में समानता नहीं है लेकिन दो दिन बाद तो सभी आंकड़े एक समान होंगे, एग्जिट पोल चलने दीजिए, सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी।एग्जिट पोल को खारिज करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली पार्टी 70 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। रामा राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 2018 में कुछ एग्जिट पोल ने गलत भविष्यवाणी की थी कि बीआरएस हार जाएगा, लेकिन परिणाम कुछ और ही साबित हुए। उन्होंने कहा, आप में से जो बीआरएस के दोस्त हैं और चाहते हैं कि केसीआर वापस आएं..., मैं आपसे वादा करता हूं कि तीन दिसंबर (मतगणना के दिन) को हम वापस आ रहे हैं। हम 70 से अधिक सीटों के साथ वापसी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने एग्जिट पोल को लेकर कहा, भाजपा 52-55 सीटों पर बढ़त लेकर सरकार बनाएगी। 75 पार वाले 40 तक पहुंच गए हैं। 2-3 सर्वे में उन्हें 40 तक दिखाया जा रहा है, लेकिन वे 75 पार कह रहे थे, अब 40 पर आकर रुक गए हैं। तीन तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें कांग्रेस 40 से भी नीचे जाने वाली है। एग्जिट पोल पर राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी ने कहा, कुछ चैनलों पर जो एग्जिट पोल जो दिखाए गए हैं, उनमें दम नहीं है। एग्टिज पोल पर नहीं जाया जा सकता है। जनता की पसंद और उनका फैसला तीन तारीख को सामने आएगा। कांग्रेस सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने कहा, यह संतोष का विषय है कि जो प्रोजेक्शन है उसमें कांग्रेस आगे है, मेरा मानना है कि 60 सीटों के आसपास कांग्रेस जाएगी। जब आप सरकार में रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है आप उम्मीदों पर पूरा खरे नहीं उतर पाते हैं, जो काम आप करते हैं उसके अलावा अगर आप जो काम आप नहीं करते हैं वह ज़्यादा दिखता है। उन्होंने आगे कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी। राजस्थान चुनौतीपूर्ण वाला है। गहलोत ने कई काम किए हैं, वहां वसुंधरा को आगे न करके गहलोत ने जो काम किया है, यह कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा। क्या इस बार टीएस सिंह देव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे? इसके जवाब में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने कहा, हाईकमान जिन्हें कहेंगे... हमने आपस में सभी राज्य नेताओं के साथ बात भी की है, सभी की यह राय है कि जो हाईकमान निर्णय लेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल पर राजस्थान मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा, मैंने अलग-अलग सर्वे देखे तो उनमें कांग्रेस आगे है। मैं लोगों को समझा रहा था कि भाजपा फर्जी सरकार है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बना रही है।

भूपेश ने प्रत्याशियों को संभालने के लिए बुक किया चार्टर प्लेन

राहुल संपाल

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे तीन दिसंबर को आएंगे। उससे पहले अलग-अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए हैं। आजतक-एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़े के अनुसार, इस बार कांग्रेस को 42, भाजपा को 41 और अन्य को 17 फीसदी वोट मिल सकते हैं। राज्य में एक बार फिर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। इस चुनाव में कांग्रेस को 40-50 सीटें, भाजपा को 36-46 सीटें जबकि अन्य के खाते में 1-5 सीटें जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में जिस तरह के नतीजे आए हैं, इसके मुताबिक कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। बघेल राज्य में सीएम फेस के लिए पहली पसंद बनकर भी उभरे हैं। हालांकि इस एग्जिट पोल में भाजपा की सीटों में बढ़त दिखाई जा रही है। इसके पीछे चुनाव के आखिरी दौर में भाजपा का आक्रमक प्रचार और पीएम की ताबड़तोड़ रैलियां मानी जा रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भाजपा के घोषणापत्र ने लोगों को विशेष रूप से आकर्षित किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले हॉर्स ट्रेडिंग से बचने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने परिणाम आते ही अपने जीते हुए प्रत्याशियों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस ने 72 सीटर वाला चार्टर प्लेन भी बुक करा लिया है। इसमें जीते विधायकों के साथ ही पार्टी के नेता भी होंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। सूत्रों की मानें तो पार्टी ने सभी प्रत्याशियों से कहा है कि जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही उसे लेकर सीधे रायपुर चले आएं। यहां के वीआईपी रोड पर एक होटल में नवनिर्वाचित विधायकों के रुकने की व्यवस्था की जा रही है। सभी प्रत्याशी रातभर एक साथ यही रुकेंगे। कांग्रेस पार्टी के बस्तर से लेकर सरगुजा तक के नवनिर्वाचित विधायकों को आने में जो समय लगेगा, इसे ध्यान में रखते हुए दूसरे दिन यानी 4 दिसंबर को सभी जीते हुए विधायकों को बेंगलुरु भेजा जाएगा। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने मध्यप्रदेश में अपनी सरकार बना ली थी। सरकार बनाने के डेढ़ साल बाद ही कुछ विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके चलते कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई थी। एमपी के अलावा महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों से सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

'जादूगर' को निर्दलियों के भरोसे रिवाज बदलने की आस

निरंजन परिहार

राजस्थान में मतदान हो चुका है और अब सरकार बदलने के रिवाज को बदलने की बात चल रही है। इसके पीछे कांग्रेस की फिर से सत्ता में आने की चाहत है। हालांकि, प्रदेश में भले ही हर पांच साल में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन अगर इस बार कांटे का मुकाबला रहता है और कांग्रेस सरकार बना पाती है तो उस सरकार की चाबी निर्दलीय और छोटे दलों के पास ही रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले दो कार्यकाल में निर्दलियों और छोटे दलों की वजह से ही गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा सके। राजस्थान की राजनीति का इतिहास रहा है कि निर्दलियों और छोटे दलों को सीधे सत्ता में सहभागिता चाहिए, इसके बिना वे समर्थन देने के लिए राजी ही नहीं होते, क्योंकि वे अपने बूते पर चुनकर आते हैं। ऐसे में खास बात यह देखने को मिली है कि उनको किसी भी राजनीतिक दल के बजाय किसी खास नेता पर ज्यादा भरोसा होता है। ऐसे में निर्दलीयों व छोटी पार्टियों में वर्तमान मुख्यमंत्री गहलोत पर भरोसा ज्यादा देखा गया है, क्योंकि उनकी सरकार में हर बार निर्दलीयों को सम्मान भी मिला और सत्ता का सुख भी प्राप्त हुआ है।

वर्ष 2008 में अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस 96 सीटों और 36.8 प्रतिशत वोट शेयर के साथ सत्ता में आई थी। उस समय निर्दलियों का वोट शेयर 15 प्रतिशत था। तब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सभी 5 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे और सरकार को बनाने व बचाने में मदद की थी। इसी तरह से वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस ने शुरुआत में 99 सीटों के साथ सरकार बनाई, तो फिर से छह बसपा विधायकों ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर इसे मजबूत किया। सन 2018 में 13 निर्दलीय जीते थे और उनका वोट शेयर भी 9.6 प्रतिशत था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जून 2020 में जब राजनीतिक संकट के दौरान, मुख्यमंत्री गहलोत को अपने डिप्टी सचिन पायलट और उनके 18

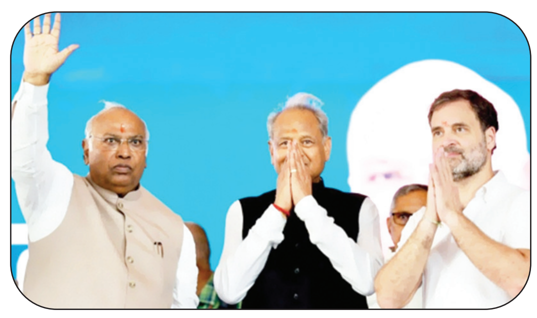

विधायकों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो 13 में से कम से कम 10 निर्दलीय विधायकों ने गहलोत सरकार को टिकाए रहने में मदद की। बाद में निर्दलीयों और छोटे दलों से कुछ विधायक मंत्री बनाए गए तो कुछ को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया गया। सरकार के समर्थन में आए पांच निर्दलीय विधायकों लक्ष्मण मीना, बाबूलाल नागर, खुशवीर सिंह, संयम लोढ़ा और ओमप्रकाश हुड़ला को इस बार 2023 के चुनाव में कांग्रेस से टिकट भी दिया गया है।

उधर, बीजेपी के कुछ नेता भी अपनी पार्टी का टिकट नहीं मिलने के बाद बागी के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। पूर्व मंत्री और वसुंधरा राजे के विश्वासपात्र युनूस खान को सन 2018 के चुनाव में उनकी सीट डीडवाना से हटाकर टोंक से सचिन पायलट के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया, वह चुनाव हार गए, जो हार लगभग तय थी। इस बार टिकट नहीं मिलने के बाद खान डीडवाना से निर्दलीय मैदान में उतरे। चित्तौड़गढ़ में वर्तमान बीजेपी विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की जगह बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नरपतसिंह राजवी को टिकट दिया गया, तो आक्या निर्दलीय मैदान में उतर गए। शाहपुरा में राजे के एक अन्य वफादार कैलाश मेघवाल को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद बीजेपी से निलंबित कर दिया गया था, तो 89 वर्षीय मेघवाल भी निर्दलीय मैदान में उतर गये।

बीजेपी से नाराज ये निर्दलीय जीते तो विधायक के रूप में किसी को भी, खासकर कांग्रेस को सत्ता दिलाने में सहजता से ताकतवर भूमिका निभा सकते हैं। कारण यही है कि बीजेपी में कोई भी नेता इस स्थिति में नहीं है, जिसकी बात पर व्यक्तिगत रूप से भरोसा करके निर्दलीय उसे समर्थन दे दें। बीजेपी के इन बागियों के अलावा, किसी भी निर्दलीय अथवा छोटी पार्टी को यह पक्का भरोसा नहीं है कि बीजेपी को समर्थन देने पर उन्हें वही सम्मान मिलेगा, जो गहलोत के राज में निर्दलीयों व छोटी पार्टियों को मिलता रहा है। फिर बीजेपी तो अपने दम पर सत्ता में आती रही है, तथा उसे निर्दलीयों और छोटे दलों तक पहुंचने की जरूरत तीस वर्षों से नहीं पड़ी।

तस्वीर साफ है कि नतीजे अगर कांग्रेस के पूरी तरह से पक्ष में नहीं भी रहे और कुछ सीटें कम भी रहीं, तो गहलोत राजस्थान के राज बदलने के रिवाज को खत्म करने का प्रयास जरूर करेंगे। ऐसे में क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या आरएलपी, हर पार्टी के नेताओं को भरोसा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अगर बहुमत के नजदीक भी पहुंचने का मौका मिला तो बीजेपी को पछाड़ते हुए जुगाड़ के जरिए फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने से नहीं चूकेंगे।

राजस्थान सहित पूरे देश की नजरें 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों पर है। हर किसी को चुनाव के नतीजों का इंतजार है। मतगणना से पहले हर सीट के गणित का हिसाब किताब लगाया जा रहा है। कौन कहां हार रहा है और कौन किस तरह से जीत रहा है। इस गणित में खास बात यह है कि किस सीट पर कौन सा निर्दलीय या छोटी पार्टी का नेता जीत रहा है, उससे अभी से संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जुगाड़ की सरकार बनी, तो ये लोग ही काम आने हैं। चुनाव जीतने की स्थिति में जो निर्दलीय वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य छोटे दल भी उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे है।

वीपी सिंह की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं अखिलेश यादव

अजय कुमार

समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। 28 नवंबर को बजट सत्र की शुरुआत होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके पीछे-पीछे उनके विधायक और पूरी पार्टी चुनावी मोड में नजर आये। अखिलेश ने जातीय जनगणना कराये जाने की मांग के सहारे अपने मंसूबे जाहिर कर दिये। सपा प्रमुख द्वारा आम चुनाव के लिए लिखी जा रही स्क्रिप्ट में जहां जातीय जनगणना के मुद्दे को राजनैतिक हवा दी जा रही है, वहीं अखिलेश यादव पूर्व प्रधानमंत्री और यूपी के मांडा के राजा स्वर्गीय वीपी सिंह को भी अपनी राजनीति का 'हथियार' बनाने में लगे हैं। जिसकी पृष्ठभूमि यूपी से कोसों दूर तमिलनाडु में लिखी जा रही है। जहां चेन्नै के एक कालेज में पूर्व पीएम की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर हिन्दी के मुखर विरोधी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूर्व पीएम वीपी सिंह की शान में कसीदे पढ़ते नजर आये और कहा कि प्रतिमा के अनावरण से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में एक स्पष्ट संदेश गया है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में सत्तर के दशक से ही ओबीसी आरक्षण पर सियासत होती रही है। वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर अखिलेश यादव को भले लग रहा हो कि इससे पूरे देश में एक खास तरह का संदेश जायेगा, परंतु यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि आज अखिलेश जिन पूर्व पीएम वीपी सिंह की याद में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनसे मुलायम सिंह यादव का छत्तीस का आंकड़ा था। नेताजी की नजरों में वीपी सिंह पिछड़ा समाज के खूनी दुश्मन थे।

इसकी वजह भी थी, जिसकी बुनियाद अस्सी के दशक में उस समय पड़ी थी, जब वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसी दौरान वीपी सिंह के एक भाई पूर्व न्यायाधीश को डकैतों ने बरगढ़ के जंगल में घेर कर मार दिया था। इसके बाद वीपी ने यूपी को दस्यु मुक्त करने के लिए बड़े स्तर पर 'दस्यु उन्मूलन अभियान' छेड़ दिया था। इस अभियान के दौरान पुलिस ने दस्यु जनक सिंह, कांता सिंह जैसे डकैतों को मौत के घाट उतार दिया था। कई डकैतों को जेल जाना पड़ा था। इस अभियान के दौरान कई नामी बदमाशों को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया था जिससे नेताजी मुलायम सिंह काफी नाराज थे। वह साफ कहते थे कि राजा मांडा दस्यु उन्मूलन अभियान के नाम पर पिछड़ों की हत्याएं करा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने दस्यु उन्मूलन के नाम पर पिछड़े वर्ग के युवाओं को पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने को ऐसा मुद्दा बनाया कि कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा और अंतत: वीपी सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। वीपी सिंह यूपी की नौकरशाही और कांग्रेस की प्राणघातक आंतरिक गुटबाजी से अज्ञात थे। मुलायम सिंह ने इन्हें अपने औजार के रूप में इस्तेमाल किया था।

वीपी सिंह और मुलायम के बीच कड़वाहट इतनी ज्यादा थी कि वीपी के कांग्रेस छोड़ने के बाद भी उनके मुलायम सिंह के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए थे। जब अमिताभ बच्चन के त्यागपत्र से रिक्त हुई इलाहाबाद लोकसभा सीट से वीपी सिंह संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार बने तो मुलायम सिंह के नाकारात्मक रुख का एहसास उन्हें निरंतर होता रहता था। इसके पीछे मुलायम सिंह की बड़ी सियासी महत्वाकांक्षा भी काम कर रही थी, मुलायम को लगता था कि मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें (मुलायम सिंह) वीपी सिंह खेमे के अधिकांश विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। फिर भी वह सीएम नहीं बन पा रहे हैं। इसी तरह से अयोध्या-राम जन्म भूमि विवाद को सुलझाने के लिए वीपी सिंह द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी मुलायम सिंह संदेह की दृष्टि से देखते थे। उन्हें हमेशा लगता रहता था कि पर्दे के पीछे वीपी सिंह उन्हें अपदस्थ करने के प्रयासों में लगे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का यह भी परिणाम हुआ कि अपनी सियासत बचाने के लिए वीपी सिंह और मुलायम को समझौता भी करना पड़ा, फिर भी समझौते के लिए किए गए सार्थक और पारदर्शी प्रयासों में भी दोनों को षड्यंत्रों की बू आती थी। शायद अब यह बातें समाजवादी पार्टी के मौजूदा नेतृत्व अखिलेश यादव के लिए कोई मायने नहीं रखती होंगी। इसीलिए वोट बैंक की सियासत में उन्हें मंडल की आग में पूरे देश को झुलसा देने वाले पूर्व पीएम वीपी सिंह ओबीसी के रहनुमा नजर आ रहे होंगे।

खैर, पहले बात उत्तर प्रदेश विधान सभा में समाजवादी पार्टी की रवैये की कि जाये तो बजट सत्र के दौरान अखिलेश ने मीडिया से रूबरू होते हुए साफ शब्दों में कहा कि जातीय जनगणना के बगैर सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह बड़ा मुद्दा रहेगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार नहीं चाहती कि हम जनता के सवाल उठाएं। यह सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है इसीलिए शीतकालीन सत्र कम दिनों का रखा गया ताकि सदन में चर्चा न हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। गौर करने वाली बात यह भी रही कि सपा विधायक सत्र के पहले दिन काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, बिजली महंगी है, आवारा जानवर सड़क पर घूम रहे हैं, अभी तक धान खरीदने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है।

बहरहाल, बात सपा विधायकों के सत्र के पहले ही दिन काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचने की कि जाये तो दरअसल इस बार विधायक विधानसभा में मोबाइल फोन वगैरह साथ नहीं ले पा रहे हैं। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए ये लोग काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंच गए। विरोध का यह सिलसिला आगे भी थमने वाला नहीं नजर आता है। बस कुछ तरीका बदल सकता है, परंतु विरोध की आग तो सुलगती रहेगी। जातीय जनगणना ऐसा मुद्दा है जिसे हथियाने की होड़ में तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ कांग्रेस भी ताल ठोक रही है। इसीलिए बिहार से लेकर यूपी और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में यह 'आग' बढ़ती जा रही है। लब्बोलुआब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आम चुनाव में धूल चटाने के लिए समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अखिलेश यादव ऐसे सभी 'दांव' आजमा रहे हैं जिससे सपा को लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर सपा द्वारा आम चुनाव के लिए तैयार की जा रही चुनावी स्क्रिप्ट में एक्शन और मसाला दोनों नजर आ रहे हैं।

संगीत में बनाएं सुरीला कैरियर

संगीत का बोलबाला पुरातन काल से रहा है। संगीत का जादू आज भी सिर चढ़कर बोलता है और धुनों पर सहसा कब शरीर में थिरकन की शुरुआत हो जाती है, इसका आभास तक नहीं हो पाता। महज मनोरंजन करने मात्र तक संगीत की अहमियत नहीं होती है। इसके अलावा मन की शांति और कई बार तो रोगियों के इलाज तक में संगीत का प्रयोग किया जाता है।

संगीत को महज शौक मानने वालों की कमी नहीं है। लेकिन विश्व के तेजी से बदलते परिदृश्य में संगीत एक महत्वपूर्ण प्रोफेशन का रूप धारण कर चुका है। खासतौर से युवाओं में इसका क्रेज आए दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है।

संगीत को अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए महज संगीत में रुचि रखना ही काफी नहीं है। इसके अलावा उन्हें सृजनात्मक प्रतिभा का धनी, धुन का पक्का, मेहनती, संगीत की समझ, वाद्ययंत्रों का ज्ञानी आदि गुणों से भरा-पूरा होना भी जरूरी है।

वर्तमान में देश-विदेश में युवाओं में म्यूजिक बैंड बनाने और परफॉर्म करने का ट्रेंड जोर पकड़ता जा रहा है। इस प्रकार के बैंडस में वोकल आर्टिस्ट (गायक) और इंस्ट्रूमैंट्रल आर्टिस्ट (वाद्ययंत्र कलाकार) दोनों का ही समन्वयन होता है। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य छोटे स्तरों पर इस प्रकार के सैकड़ों हजारों बैंडस आज अस्तित्व में आ चुके हैं।

अमूमन यही माना जाता है कि संगीत को करियर का आधार बनाकर ज्यादा कुछ करने की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। अगर वास्तविकता के धरातल पर बात करें तो कम से कम आज के संदर्भ में स्थितियां बहुत भिन्न हैं और तमाम नए विकल्प उबरकर सामने आ चुके हैं। आइए दृष्टि डालते हैं इन संगीतमय करियर विकल्पों परः-

स्टूडियो टीचिंग

म्यूजिक टीचर के रूप में स्कूलों कॉलेजों और अन्य संगीत प्रशिक्षण संस्थाओं में करियर बनाने के बारे में भी सोचा जा सकता है। इनमें भी विशेषतता प्राप्त टीचर का खासा महत्व होता है। विशेषताओं में खासतौर पर म्यूजिक थ्यरी, म्यूजिक हिस्ट्री एंड लिट्रेचर, म्यूजिक एजुकेशन, म्यूजिकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, कंपोजिशन अथवा म्यूजिक थेरेपी की बात की जा सकता है। इन सबके अतिरिक्त फिल्म इंडस्ट्री, चर्च म्यूजिशियन म्यूजिक लाइब्रेरियन, म्यूजिक अरेंजिंग, म्यूजिक सॉफ्टवेयर, प्रोडेक्शन म्यूजिक, वर्चुअल रिअल्टी साउंड एंवायरनमेंट इत्यादि जैसी विधाओं में भविष्य बनाया जा सकता है।

म्यूजिक इंडस्ट्री

इस उद्योग में कई प्रकार के म्यूजिक आधारित प्रोफेशनलों की अहम भूमिका होती है, इनमें विशेष तौर पर म्यूजिक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, कंपोजर, म्यूजिशियन, जैसे कार्यकलापों के अलावा म्यूजिक बुक्स की पब्लिशिंग, म्यूजिक अलबम रेकार्डिंग म्यूजिक डीलर, म्यूजिक स्टूडियो के विभिन्न विभागों इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है।

टेलीविजन

साउंड रिकार्डिस्ट, म्यूजिक एडिटर, प्रोडक्शन, आर जे एवं डीजे म्यूजिक लाइसेंस में ऐसे जानकार और अनुभवी लोगों की जरूरत पड़ती है।

स्टेज परफार्मेंस

म्यूजिक शो, टेलीविजन म्यूजिक प्रोग्राम, म्यूजिक कंपीटिशन आर्म्ड फोर्सेज बैंडज, सिंफनी आर्केस्ट्रा, डांस बैंड, नाइटक्लब, कसर्ट शो, रॉक और जैज ग्रुप इत्यादि में भी इनकी भूमिका का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

म्यूजिक थेरेपिस्ट

विकलांगता के शिकार बच्चों और लोगों के अलावा मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के उपचार में आजकल संगीत को काफी महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। इस प्रोफेशन में सफल होने के लिए संगीत, अध्यायन और थेरेपी का जानकार होना जरूरी है। इनके लिए हॉस्पीटलों, मेंटल टैम्थ सेंटरों, नर्सिंग होम्स इत्यादि में रोजगार के अवसर हो सकते हैं।

फैशन डिजाइनिंग में बनाए अपना कैरियर

फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते है। इस क्षेत्र में फैशन डिजाइनिंग से जुड़े स्नातक स्तर के कोर्स होने चाहिए। हम आपको फैशन डिजाइनिंग से जुड़ी कई जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग में बनाए अपना कैरियर, अब डिग्री कोर्स भी संभव

फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कदम

फैशन डिजाइनिंग उन टॉप विकल्पों में शामिल है, जो महिलाओं द्वारा करियर के रूप में बेहद पसंद किया जाता है। किसी भी विषय से बारहवीं पास करने के बाद फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कदम रखा जा सकता है।

इस क्षेत्र में तह्डुस्रह्डुह्लद्धश्ठ्ठ ष्श्हह्ह्यद्द के लिए अहमदाबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी ह्द्धष्ठ एक उत्कृष्ट संस्थान है, हालांकि अब इसके दो नए केंद्र भी कार्यरत हैं, जो कुरुक्षेत्र और विजयवाड़ा में हैं। 10+2 के बाद यहां से दो पाठ्यक्रम किए जा सकते हैं- बैचलर इन डिजाइन और ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम इन डिजाइन यानी जीडीपीडी।

प्रवेश जांच परीक्षा को डैट

इन दोनों पाठ्यक्रमों की अवधि 4 वर्ष है और इनमें प्रवेश के लिए आपको दो-स्तरीय प्रवेश जांच परीक्षा से गुजरना होगा। इस प्रवेश जांच परीक्षा को डैट यानी डिजाइन एप्टिट्यूड टेस्ट कहा जाता है। नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया सितम्बर से ही प्रारंभ हो जाती है, जिसके बाद जनवरी में प्रारम्भिक परीक्षा और फिर मई में मुख्य परीक्षा आयोजित कर नामांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाता है।

डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन

ह्द्धष्ठ के अतिरिक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से 4 वर्षीय बी. डेस. और पर्ल इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग में ही ग्रेजुएशन कोर्स किया जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए सम्बंधित कॉलेज की वेबसाइट खंगालें।

एप्स डेवलपर सर्वश्रेष्ठ कैरियर विकल्प

युवा पीढ़ी में एप्स की डिमांड जिस प्रकार तेजी से बढ़ रही है इस फील्ड में करियर की संभावनाएं भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। आज रेलवे टिकट बुक कराने से लेकर मूवी के टिकट तक के लिए युवा एप्स का इस्तेमाल करते हैं। चेन्नई, बेंग्लुरू, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। धीरे-धीरे इन एप्स का चलन देश के बाकी शहरों की ओर भी बढ़ रहा है।

एप्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इसे पाठ्यक्रम के रूप में भी शामिल किया जा रहा है। सर्च इंजन गूगल के अनुसार इस समय भारत में चार करोड़ भारतीय अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और एक सप्ताह में करीब तीन करोड़

एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल के एप्लीकेशन स्टोर से अब तक 40 बिलियन एप्स डाउनलोड किए जा चुके हैं जो पहले से काफी ज्यादा है। पिछले कुछ समय में तो एक नया रिकार्ड बना जब डाउनलोड का यह आंकड़ा 2 बिलियन को छू गया।

इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक भारतीय यूजर इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए दिन में लगभग 52 मिनट खर्च करता है और यही कारण है कि एप्स की मांग बढ़ने से कंपनियों की जमकर कमाई भी हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल भारतीय इंडस्ट्री में लगभग 2 लाख 50 हजार डेवलपर काम कर रहे हैं और बढ़ती डिमांड को देखते हुए अतिरिक्त डेवलपर्स की जरूरत होगी। ऐसे में एप्स में करियर, पैसा और प्रगति दोनों उपलब्ध कराएगा।

क्या है मोबाइल एप्लीकेशन

दरअसल एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग अलग-अलग रूप में मोबाइल डिवाइस, गूगल एंड्राइड, आइपैड और आईफोन के आपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है। वैसे आसान रूप में तो मोबाइल एप्लीकेशन दो तरह के होते हैं। नेटिव, एप्पल, आइओएस या गूगल एंड्राइड जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तैयार किये जाने वाले एप्स पहले समूह में आते हैं और दूसरे वर्ग में मोबाइल वेब शामिल हैं जहां एचटीएमएल जैसी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है और चलाने के लिए ब्राउजर की जरूरत होती है।

मोबाइल डेवलपर का कार्य

मोबाइल डेवलपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होते हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन की डिजाइन विकसित करने के साथ-साथ एक या एक से अधिक मोबाइल ऑप्रेटिंग सिस्टम और डिजाइंस जैसे एप्पल, आईओएस या गूगल एंड्राइड पर इनकी जांच करते हैं। बाजार में लांच होने के बाद एप्स यूजर्स से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को समझते हैं। यूजर्स की जरूरतों के अनुसार उनमें परिवर्तन करते हैं। इसके अलावा नए संस्करण भी तैयार करते हैं।

अवसर

इस सेक्टर में काम करने के केंद्र मुख्य रूप से एम-वैस (मोबाइल वैल्यू ऐडेड सर्विसेज) इंडस्ट्री और आईटी कंपनियां हैं। आप अपने काम की तलाश मोबाइल ऑपरेटर, मोबाइल डेवलपमेंट एप्लीकेशन कंपनियों और वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रदाता कंपनियों में कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस क्षेत्र में जिस तेजी से मांग बढ़ रही है उसकी तुलना में पर्याप्त आपूर्ति बहुत कम है। यहां आप मोबाइल यूआई डिजाइनर और यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजेबिलिटी विशेषज्ञ के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में इंजीनियर और मोबाइल आर्किटेक्ट के रूप में भी अपने करियर को एक बेहतर मुकाम तक ले जा सकते हैं।

योग्यता

आईओएस (आईपैड, आईफोन) या जावा (एंड्राइड, ब्लैकबेरी ओएस) पर एप्लीकेशंस लिखने के लिए सी, सी प्लस, आब्जेक्टिव सी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड होना बहुत जरूरी है। आपकी यूआई डिजाइन के बेसिक्स और एप्लीकेशन डिजाइन के बेसिक्स पर भी अच्छी कमांड होनी चाहिए।

एक बार आप बेसिक को समझ लेते हैं, तो उसके बाद आपको प्लेटफार्म और मोबाइल सिस्टम चुनना होगा। यदि आप आईफोन और आईपैड डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव-सी एक्सकोड और मैक ओएस एक्स प्लेटफार्म पर इंटरफेस के निर्माण का हुनर सीखना होगा। यदि आप गूगल एंड्राइड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको जावा में प्रवीण और एंड्राइड डेवलपमेंट में दक्ष होना होगा।

इसके अलावा एक अच्छा डिजाइनर बनने के लिए आपके पास कलात्मक और रचनात्मक हुनर होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में बीई, बी.टेक, एम.टेक, एमसीए या आइटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर इस फील्ड में करियर बना सकते हैं।

सैलेरी

इस क्षेत्र में प्रोफेशनल डेवलपर के तौर पर शुरुआत में 3 से 5 लाख रुपये सालाना की कमाई कर सकते हैं। जिन डेवलपर्स को दो से तीन साल का एक्सपीरियंस होता है वे आसानी से 4-7 लाख रुपये सालाना तक कमा लेते हैं। आपकी सैलेरी पूरी तरह आपके टेक्निकल नॉलेज पर निर्भर करती है। जैसे-जैसे आपके अनुभव व योग्यता में बढ़ोतरी होती है, आपकी कमाई में भी इजाफा होता है।

संस्थान

एनआईआईटी, गुड़गांव
कोडफक्स, बेंग्लुरू
जीनियस पोर्ट, पुणो व बेंग्लुरू
भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, पुणे

खूबसूरत बाल पाने के लिए इस आसान तरीके से घर पर करें हेयर स्पा, मिलेगी बेहतरीन शाइन

हर मौसम में अपने बालों का ख्यास ख्याल रखना पड़ता है। बालों का ख्याल रखने के लिए हम सभी ना जाने कितने हेयर प्रोडक्ट और हेयर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर बात बालों की देखभाल की हो, तो इसके लिए हमें मार्केट में कई तरह की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। लेकिन इनके अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आप बिना किसी नुकसान के बालों की देखभाल करना चाहते हैं, तो आप कम खर्चे में आसानी से घर पर भी हेयर स्पा कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हेयर स्पा हमारे बालों को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। वहीं ऑलिव ऑयल बालों को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। ऐसे में अगर आप भी हर पर हेयर स्पा लेना चाहते हैं। तो यह आर्टिकल आपके लिए है, आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको घर पर हेयर स्पा करने का तरीका बता रहे हैं। इससे आप स्मूथ और शाइनी हेयर पा सकते हैं।

आवश्यक सामग्री

ऑलिव ऑयल- 2 से 3 चम्मच केले- 2 से 3

ऑलिव ऑयल के फायदे

- आपको बता दें कि ऑलिव ऑयल में एंटी-फंगल तत्व पाए जाते है, जो आपके बालों को डैंड्रफ से बचाने में सहायक होता है।
- वहीं ऑलिव ऑयल आपके बालों को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के साथ ही बालों को मॉइश्चराइज देने का काम करता है।
- ऑलिव ऑयल के रोजाना इस्तेमाल से बाल शाइनी और स्मूथ होते हैं।

बालों में केला अप्लाई करने के फायदे

- बता दें कि बालों में केला अप्लाई करने से आपके बाल स्मूथ और शाइनी बनते हैं। क्योंकि केले में विटामिन सी पाया जाता है।
- इससे बालों की फ्रिजीनेस कम होती है।
- केले में मौजूद एंटीमाइक्रोबियल गुण आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है।
- इसमें मौजूद एंटी-फंगल प्रॉपर्टी खुजली को कम करने में मदद करता है।
- इस तरह से केला और ऑलिव ऑयल बालों को अच्छे से पोषण देने में मदद करता है।

कैसे करें हेयर स्पा

- घर पर हेयर स्पा करने के लिए सबसे पहले 2-3 केले को एक बाउल में मैश कर लें।
- फिर मैश किए हुए केले में 3 चम्मच ऑलिव ऑयल मिक्स कर लें।
- इसके बाद इसको अपने बालों की लेंथ में अप्लाई करें।
- फिर इसे बालों में 15-20 मिनट तक लगा रहने दें।
- इसके बाद 10 मिनट बालों को स्टीम करें और फिर तौलिए की मदद से बालों को कवर कर लें।
- अब 10 मिनट तक तौलिए से कवर करने के बाद पानी की मदद से बालों को धो लें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राज्यसभा ने अपने सांसदों के लिए जारी की अधिसूचना

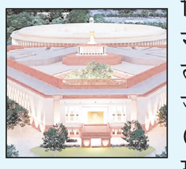

नईदिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र से कुछ दिन पहले, राज्यसभा ने अपने सदस्यों को विदेश यात्रा, यहां तक कि निजी यात्रा पर भी जाने से पहले विदेश मंत्रालय (एमईए) से राजनीतिक मंजूरी लेने की याद दिलाई। नयी अधिसूचना में कहा गया है कि सांसदों को निजी विदेश यात्रा के दौरान विदेशी आतिथ्य स्वीकार करते समय सख्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा तथा केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। राज्यसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बुलेटिन अपने सांसदों के लिए 2005 की आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा किसी भी विदेशी स्रोत, अर्थात् किसी भी देश की सरकार या किसी विदेशी इकाई से सभी निमंत्रण विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाने की उम्मीद है। हालाँकि, यदि ऐसा निमंत्रण सीधे प्राप्त होता है, तो सदस्यों को इसे विदेश मंत्रालय के ध्यान में लाना आवश्यक है और इस उद्देश्य के लिए उस मंत्रालय की आवश्यक राजनीतिक मंजूरी भी प्राप्त की जानी चाहिए।

राघव चड्ढा निलंबन मामले में सुनवाई आठ दिसंबर तक टली

नई दिल्ली। राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई 8 दिसंबर तक के लिए स्थगित करने का फैसला चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में हुई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष राज्यसभा सचिवालय की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस मामले में कुछ रचनात्मक प्रगति की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अगर अदालत इस मामले की सुनवाई बाद में कर सकती है, तो कई मुद्दों पर विचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले के बारे में कुछ न कहें... बस इंतजार करें। आइए एक समाधान निकालें। इस टिप्पणी के साथ पीठ ने याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख आठ दिसंबर तय की। सुप्रीम कोर्ट में राघव चड्ढा की तरफ से अदालत में पेश हुए वकील शादान फरासत ने राज्यसभा सांसद के आधिकारिक बंगले से बेदखली की नोटिस का मुद्दा भी उठाया।

सपा पर बरसे योगी, गलत तथ्य रखने का लगाया आरोप

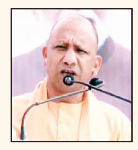

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि डबल इंजन सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य के प्रति धारणा बदल गई है और आज लोग यूपी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सीएम योगी ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी (समाजवादी पार्टी) सरकार विधानसभा में गलत तथ्य पेश करती थी और लोग उनके कुकर्मों को नहीं भूले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार रही। आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा कि हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, आर्थिक प्रगति करेगा तो विपक्षियों को भी खुश होना चाहिए। योगी ने कहा कि 2016-17 में यूपी की जीएसडीपी करीब 13 लाख करोड़ रुपये थी। आज 2023-24 में ये करीब 24.5 लाख करोड़ रुपये है। राज्य का बजट बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि कुल में से देश की 16 फीसदी आबादी राज्य में रहती है।

कांग्रेस की जीत इंडिया ब्लॉक की जीत होगी : संजय राउत

मुंबई। पिछले महीने हुए पांच विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान जीतने की भविष्यवाणी के एक दिन बाद, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि कि सबसे पुरानी पार्टी की जीत इंडिया ब्लॉक की जीत होगी, जिसमें 25 से अधिक विपक्षी दल शामिल हैं। ऐसा तब हुआ है जब अधिकांश एग्जिट पोल में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई थी, जबकि अधिकांश ने राजस्थान में भाजपा की सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी की थी। एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों का हवाला देते हुए, राउत ने कहा कि कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं और उनकी जीत उस विपक्षी गठबंधन की जीत है जो 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को हराने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं, ये समझने के लिए हमें किसी एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने गतिरोध सुलझाने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री से मिलने को कहा

नईदिल्ली। तमिलनाडु बिल विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की विधानसभा द्वारा दोबारा अपनाए गए बिल को राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को नहीं भेज सकते। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलने और गतिरोध को हल करने के लिए भी कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को करेगी। पीठ ने कहा कि हम चाहेंगे कि राज्यपाल गतिरोध दूर करें। अगर राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ गतिरोध सुलझाते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे। मुझे लगता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को आमंत्रित करते हैं; उन्हें बैठकर इस पर चर्चा करने दीजिए। पीठ ने यह भी कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि हम उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं।

बीएसएफ स्थापना दिवस पर बोले केंद्रीय गृहमंत्री

जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं वह कभी भी विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता : शाह

रांची। झारखंड के हजारीबाग जिले में बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बीएसएफ स्थापना दिवस पर हजारीबाग के झांसी रानी परेड मैदान में समारोह का आयोजन किया गया था, जहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान प्राणों का बलिदान देने वाले बीएसएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी और परेड की सलामी ली। परेड में बीएसएफ के सभी फ्रंटियर के महिला-पुरुष की टुकड़ियों ने भाग लिया। जवानों ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाये। बीएसएफ एयरविंग हेलीकॉप्टर, ऊंट व घुड़सवारी दस्ते, मोटरसाइकिल टीम, डॉग दस्ता, पैरागैलाइडिंग समेत अन्य दस्तों का भी प्रदर्शन हुआ। बीएसएफ के जवानों को सम्मानित भी किया गया। वहीं, शहीद के परिजनों को पुलिस मेडल फॉर मेडल-पीएमजी मरणोपरांत प्रदान किया गया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश की सीमा की देखभाल करने के लिए सीमा सुरक्षा बलों (बीएसएफ) की सराहना की, जिसके कारण वह बिना किसी तनाव के शांति से सो पाते हैं। बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग में अर्धसैनिक बल के जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार जब सीमाओं के रक्षक मोर्चा संभाल लेंगे तो देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर बीएसएफ के सभी जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरे देश को हमारे जवानों पर गर्व है।

गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ के अधीन आने वाली पाकिस्तान सीमा हो या बांग्लादेश सीमा, जब भी दुश्मन कोई हरकत करता है तो स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है लेकिन जब बीएसएफ कहती है कि उनके जवान मौजूद हैं तो मैं बिना किसी तनाव के चैन की नींद सो पाता हूं। उन्होंने कहा कि एक बार जब सीमा के रक्षक मोर्चा संभाल लें तो किसी को भी सीमा की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। एक गृह मंत्री के रूप में मुझे आप पर बहुत गर्व है।

अमित शाह ने कहा कि यदि किसी देश की सीमाएँ सुरक्षित नहीं हैं तो वह कभी भी विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। चाहे जी 20 का सफल आयोजन हो या चंद्रयान-3, ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि आपके त्याग और तपस्या से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। बीएसएफ इस देश के विकास की जड़ है। उन्होंने कहा कि कल, मैंने वामपंथी उग्रवाद के साथ हमारी लड़ाई की समीक्षा की। आज मैं बताना चाहता हूं कि हम इसके कगार पर हैं। वह दिन दूर नहीं जब देश वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह मुक्त हो जायेगा।

शाह ने कहा वामपंथी उग्रवाद दिन-ब-दिन सिमटता जा रहा है। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ अपने अंतिम हमले के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में देश को इससे मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं... गश्त बढ़ने से उग्रवादियों के संसाधनों में कमी आई है... झारखंड के कुछ इलाकों में आखिरी लड़ाई बाकी है. हम वह लड़ाई भी जीतेंगे। बीएसएफ स्थापना दिवस के कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल हजारीबाग के विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया।

बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह में बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि सीमा पार से गोलीबारी की हालिया घटनाओं में, बीएसएफ ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएसएफ ने हथियारबंद घुसपैठियों को भी मार गिराया। पिछले एक साल में, बीएसएफ ने पाकिस्तान से आ रहे 90 ड्रोनों को मार गिराया और 1000 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। भारत-बांग्लादेश सीमा पर पिछले एक साल में 20 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किया गया। 150 किलोग्राम से अधिक सोना भी बरामद किया गया।

बीएसएफ की वीरता और अटूट भावना उसके समर्पण का प्रमाण : मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 59वें स्थापना दिवस पर शुक्रवार को इस उत्कृष्ट बल की सराहना की और कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बीएसएफ के स्थापना दिवस पर हम इस उत्कृष्ट बल की सराहना करते हैं, जिसने हमारी सीमाओं के संरक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण है। मैं प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर बचाव और राहत कार्य के दौरान बीएसएफ की भूमिका की भी सराहना करना चाहूंगा। बीएसएफ की स्थापना वर्ष 1965 में भारत की सीमाओं की रक्षा और अन्तरराष्ट्रीय अपराध को रोकने के लिए की गई थी। बीएसएफ केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश की आज़ादी में 'सीमा सुरक्षा बल' की अहम भूमिका अविस्मरणीय है।

महिला कांग्रेस की रैली में बोले राहुल गांधी

हमारा लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 50 फीसदी मुख्यमंत्री महिलाएं हों

तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एर्नाकुलम में उत्साह महिला कांग्रेस के राज्य सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सत्ता में महिला की कमी पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास महिला मुख्यमंत्रियों की कमी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लिए एक अच्छा लक्ष्य होगा अगर आज से अगले 10 वर्षों में हमारे पास 50 फीसदी मुख्यमंत्री महिलाएं हों। हमारे पास बहुत कम महिला मुख्यमंत्री हैं। पर मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी में कई महिलाएं हैं, जो एक अच्छी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। राहुल ने आगे कहा कि एकमात्र कमी यह है कि मंच पर पुरुष हावी हैं, जोकि अच्छी बात है, लेकिन अब हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि कांग्रेस पार्टी के हर स्तर पर अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी हो।

इससे पहले, केरल के नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीसन ने बताया कि रैली का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को उजागर करना है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ महिला कांग्रेस के वार्ड स्तर के सभी पदाधिकारी रैली में शामिल होंगे। हमारी रैली उन सरकारों के लिए चेतावनी है, जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसाओं को रोकने में विफल रही है।

दो दिन पहले, केरल के नीलांबुर ब्लॉक पंचायत में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ये चार परियोजनाएं लोगों के हित में हैं। पहली- लोगों के लिए एक उपशामक देखभाल, दूसरी आदिवासी प्रसवरोधी गृह परियोजना (इस योजना का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना), अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सामान्य स्वास्थ्य देखभाल परियोजना साथ ही अंतिम परियोजना आदिवासी बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल परियोजना है।

राहुल ने कहा कि यह पहली बार है जब मैंने संसद में कोई विधेयक पारित होते देखा है जिसे एक दशक बाद लागू किया जाएगा। भाजपा जिस एकमात्र

विधेयक को पारित होने के 10 साल बाद लागू कर रही है, वह महिला शक्ति से संबंधित है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य लड़ाई यह है कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की तस्वीरों में आप महात्मा गांधी जी को हमेशा महिलाओं के साथ खड़े देखेंगे। आजादी की लड़ाई में महिलाएं सबसे आगे थीं।

पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस में कई महिला अध्यक्ष रहीं। महिलाओं को सत्ता संरचना का हिस्सा होना चाहिए। आरएसएस के इतिहास में, इसने कभी भी महिलाओं को अपने खेमे में आने की अनुमति नहीं दी है। आरएसएस में महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा कि हम मूलत: महिलाओं को सत्ता संरचना में लाना चाहते हैं। हमारी अधिकांश योजनाएं महिलाओं की सहायता के लिए बनाई गई हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि आज के राजनीतिक माहौल में, जो नफरत और हिंसा से भरा हुआ है, महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। यह महत्वपूर्ण है कि महिला कांग्रेस हमारे विपक्ष द्वारा प्रचारित नफरत और हिंसा के माहौल से लड़े। मैं उन लाखों कांग्रेस महिलाओं को धन्यवाद देता हूं जो हर दिन हमारी विचारधारा के लिए लड़ती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी होने का क्या मतलब है? हम दूसरों से कैसे भिन्न हैं? जवाब में उन्होंने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में जर्मनी से हारी भारतीय टीम

सैंटियागो। दो गोल की बढत बनाने के बावजूद भारतीय टीम एफआईएच हॉकी महिला जूनियर विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में पिछली उपविजेता जर्मनी से 3 . 4 से हार गई। भारत के लिये अन्नु (11वां मिनट), रोपनी कुमारी (14वां मिनट) और मुमताज खान (24वां मिनट) ने गोल किये जबकि जर्मनी के लिये सोफिया श्वाबे (17वां), लौरा प्लथ (21वां और 36वां) और कैरोलिन सेइडेल (38वां) ने गोल दागे।

पहले मैच में कनाडा को 12. 0 से हराने वाली भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर में दबदबा बना लिया और जर्मनी की रक्षापंक्ति को खासा परेशान किया। इन हमलों के बीच भारत को लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिले और दूसरे पर अन्नु ने गोल करके टीम को बढत दिलाई। इसके तीन मिनट बाद रोपनी ने गोल करके पहले क्वार्टर में भारत की बढत 2 . 0 की कर दी।

दूसरे क्वार्टर में जर्मनी के लिये सोफिया ने दूसरे ही मिनट में फील्ड गोल दागा। वहीं लौरा ने बराबरी का गोल किया। मुमताज ने हालांकि 24वें मिनट में गोल करके हाफटाइम तक भारत को फिर 3 . 2 की बढत दिला दी। तीसरे क्वार्टर में भारत का जोर गेंद पर नियंत्रण बनाये रखने पर रहा जबकि जर्मनी ने बराबरी का गोल दाग दिया। लौरा ने 36वें मिनट में यह गोल किया। कैरोलिन ने 38वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके जर्मनी को बढत दिलाई।

आखिरी क्वार्टर में दोनों टीमों ने काफी आक्रामक खेल दिखाया लेकिन गोल नहीं हो सका। भारतीय गोलकीपर माधुरी किंडो ने शानदार प्रदर्शन करके जर्मनी को एक और गोल करने से रोका। भारत को आखिरी क्षणों में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन गोल नहीं हो सका। भारत का सामना अब शनिवार को बेल्जियम से होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 493 अंक चढ़ा निफ्टी ऑल टाइम हाई पर

नईदिल्ली। दिसंबर महीने के पहले और इस सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन घरेलू बाजार हरे निशान में बंद हुए। सितंबर तिमाही के लिए उम्मीद से बेहतर आए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों ने बाजार को सपोर्ट किया। इसके अलावा विदेशी बाजारों से मिले मजबूत संकेत भी मार्केट में उछाल के लिए जिम्मेदार रहे। 30 शेयरों वाला क्रस्श सेंसेक्स 492.75 अंकों की उछाल के साथ 67,481.19 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 इंट्रा-डे में आल टाइम हाई पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 शुक्रवार को 134.75 अंकों की तेजी के साथ 20,267.90 पर बंद हुआ। नवंबर में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के बेहतर आंकड़ों ने भी बाजार के सेंटीमेंट को मजबूत किया। अक्टूबर में सुस्ती के बाद, ग्राहकों की बढ़ती मांग और इनपुट की बेहतर उपलब्धता के कारण नवंबर में पीएमआई 55.5 से बढ़कर 56.0 हो गया।

एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े विमान ईंधन 4.6% हुआ सस्ता

नईदिल्ली। विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत में शुक्रवार को 4.6 प्रतिशत की कटौती की गई। वहीं वाणिज्यिक इस्तेमाल वाले 19 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) का दाम 21 रुपये बढ़ाया गया है। हालांकि, घरेलू इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) का दाम 903 रुपये पर कायम रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) का दाम 1,06,155.67 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया है, जो पहले 1,11,344.92 रुपये प्रति किलोलीटर था। वहीं होटल तथा रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल किए जाने वाले वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत 1,775.50 रुपये से बढ़कर 1,796.50 रुपये प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर हो गई है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल थोक बिक्री नवंबर में 21 प्रतिशत बढ़ी

नईदिल्ली। महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) लिमिटेड की नवंबर में कुल थोक बिक्री सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 70,576 इकाई रही। कंपनी ने नवंबर 2022 में 58,303 इकाइयों की आपूर्ति की थी। एमएंडएम की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, मोटर वाहन निर्माता ने पिछले महीने यूटिलिटी वाहनों की 39,981 इकाइयों की आपूर्ति की। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना से 32 प्रतिशत अधिक है, जब कंपनी ने 30,238 इकाइयों की आपूर्ति की थी। हालांकि, नवंबर में निर्यात 42 प्रतिशत घटकर 1,816 इकाई रह गया, जबकि नवंबर 2022 में यह 3,122 इकाई था। एमएंडएम के वाहन खंड के अध्यक्ष विजय नाकरा ने कहा, '' एसयूवी खंड में मजबूत मांग से वृद्धि जारी रही। हालांकि, त्योहारी सीजन अच्छा रहा लेकिन इस महीने चुनिंदा हिस्सों में आपूर्ति संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

अक्टूबर के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार

नईदिल्ली। नवंबर में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रदर्शन में सुधार देखा गया। अक्टूबर में मंदी के बाद, ग्राहकों की बढ़ती मांग और इनपुट की बेहतर उपलब्धता के कारण उत्पादन वृद्धि में तेजी आई, जिससे उत्पादन मात्रा में वृद्धि हुई। नवंबर में, भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अक्टूबर की धीमी गति से वापसी की, एसएंडपी ग्लोबल पीएमआई 55.5 से बढ़कर 56.0 हो गया। यह बेहतर ऑपरेटिंग कंडीशन को दर्शाता है, हालांकि यह दूसरी तिमाही के औसत 57.9 से थोड़ा कम है। कुल मिलाकर, चीजें बेहतर दिख रही हैं। यदि रीडिंग 50 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ग्रोथ है, और यदि यह 50 से नीचे है, तो यह गिरावट का संकेत है। मुद्रास्फीति का दबाव शांत हो गया, और खरीद की लागत अगस्त 2020 के बाद से सबसे धीमी दर से बढ़ी।

आत्मनिर्भर के कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया

प्रह्लाद सबनानी

वित्तीय वर्ष 2023-24 की द्वितीय तिमाही, जुलाई-सितम्बर 2023 के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के आंकड़े भारत सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इस वर्ष द्वितीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए अनुमानों से बहुत ऊपर रही है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए 6.8 प्रतिशत के अनुमान से बहुत अधिक अर्थात यह वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत की रही है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही में 6.2 प्रतिशत की रही थी। भारत में इस वर्ष द्वितीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में दर्ज की गई वृद्धि की तुलना में अन्य देशों के सकल घरेलू उत्पाद में तिमाही के दौरान वृद्धि दर बहुत कम रही है। फिलिपींस में 5.9 प्रतिशत, रूस में 5.5 प्रतिशत, वियतनाम में 5.33 प्रतिशत, अमेरिका में 5.2 प्रतिशत, चीन में 4.9 प्रतिशत, मलेशिया में 3.3 प्रतिशत, थाईलैंड में 1.5 प्रतिशत, ब्रिटेन में 0.6 प्रतिशत, यूरो क्षेत्र में 0.1 प्रतिशत, जर्मनी में रिणात्मक 0.4 प्रतिशत एवं जापान में रिणात्मक 2.1 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की गई है। इस प्रकार भारत पूरे विश्व में लगातार सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

हर्ष का विषय तो यह है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जुलाई-सितम्बर 2023 तिमाही के दौरान 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर में मुख्य योगदान उद्योग क्षेत्र का रहा है। भारत के उद्योग क्षेत्र ने इस दौरान 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है, जोकि हाल ही के समय में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही, जुलाई-सितम्बर 2022 के दौरान उद्योग क्षेत्र ने रिणात्मक 0.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की थी। उद्योग क्षेत्र के

अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र ने 13.9 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान रिणात्मक 3.8 प्रतिशत थी। ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र ने 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर, माइनिंग क्षेत्र ने 10 प्रतिशत, कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र ने 13.3 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर हासिल की है। इन समस्त क्षेत्रों में रिकार्ड वृद्धि दर से भारत में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित हुए हैं, जिसके चलते बेरोजगारी की दर में भी कमी दृष्टिगोचर हुई है। भारत में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर-नवम्बर माह में दीपावली एवं अन्य कई महत्वपूर्ण त्यौहारों का मौसम रहता है। इन त्यौहारों के दौरान भारत के नागरिकों द्वारा विभिन्न उत्पादों की भारी मात्रा में खरीददारी की जाती है। ऐसा आभास है कि अकटोबर-नवम्बर में पड़ने वाले विभिन्न त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए जुलाई-सितम्बर 2023 तिमाही में ऑटोमोबाइल, फ्रिज, टीवी, मोबाइल फोन, आदि जैसे विभिन्न उत्पादों का भारी मात्रा में उत्पादन विनिर्माण इकाईयों द्वारा किया गया है। जिसके चलते इस तिमाही में विनिर्माण इकाईयों ने भारी भरकम 13.9 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। भारत में कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र ने भी रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते इस क्षेत्र में आकर्षक 13.3 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर ली गई है। अक्टूबर 2023 माह में भी कोर क्षेत्र के उद्योगों ने 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की द्वितीय तिमाही में सेवा क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई वृद्धि दर ने जरूर निराश किया है। इस दौरान सेवा क्षेत्र ने 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज की गई वृद्धि दर 9.4 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। इस वर्ष द्वितीय तिमाही में हासिल की गई वृद्धि दर से आश्चर्य भी हुआ है क्योंकि विभिन्न बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋणों में वृद्धि दर लगातार दहाई के आंकड़े पर बनी हुई है, होटल लगातार अपनी स्थापित क्षमता का भरपूर उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रेलवे एवं हवाई जहाज का उपयोग भी लगातार उच्चत्तम स्तर पर बना हुआ है। फिर भी, वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र ने 6 प्रतिशत एवं व्यापार एवं होटल क्षेत्र ने 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में अंतिम उपभोग में भी केवल 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की जा सकी है। भारत को यदि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देखना है तो भारत के निजी क्षेत्र के लिए अपने उपभोग में वृद्धि करना अब आवश्यक हो गया है।

ये दबदबा,ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलतें..... सब किरायेदार हैं, घर बदलते रहते हैं.....

देश के 5 विधानसभा चुनाव के असल नतीजे तो 3 दिसंबर को आने वाले हैं लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स से इन चुनावों में जनता का मूड जरूर पता चल रहा है छत्तीसगढ़,मप्र राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा में जनता का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है।अलग अलग एग्जिट के आधार पर %पोल ऑफ पोल्स% के नतीजों को ही यदि परिणाम मान लिया जाए तो छत्तीसगढ़,राजस्थान और तेलंगाना में कॉंग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है तो मप्र में भाजपा की सरकार बन सकती है वहीं मिजोरम में भाजपा समर्थित पार्टी की सरकार बन सकती है।छग में कांग्रेस की सरकार फिर से बनती दिख रही है।वहीं मप्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है।लेकिन पोल ऑफ पोल्स में यहां फिर से शिवराज सरकार का अनुमान है। राजस्थान में मुकाबला कांटे का है।पर यहां कांग्रेस की फिर सरकार बन सकती है।तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है।हालांकि ये केवल एग्जिट पोल्स के अनुमान हैं और मतगणना के दिन अंतिम परिणाम सामने आएगा....?

छत्तीसगढ़ और मिथक का बनना-बिगड़ना....?

छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया राज्य बनने के पहले तथा बाद में कुछ मिथक हर बार चर्चा में रहते हैं। पहला मिथक विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा मिथक नेता प्रतिपक्ष,तीसरा मिथक पंचायत मंत्री,चौथा मिथक महिला बाल विकास मंत्री को लेकर है, देखना यह है कि 3 दिसम्बर को क्या होता है....? नया छत्तीसगढ़ राज्य बना तो पहले विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला बने। 2003 को छग के पहले विस चुनाव में वे जीत गये पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी उसके बाद लगातार विधानसभा अध्यक्ष अगला चुनाव हारते आ रहे हैं।भाजपा की पहली सरकार बनी प्रेम प्रकाश पांडे विस अध्यक्ष बने पर 2008 का अगला चुनाव वे हार गये।2008 में धरमलाल कौशिक विस अध्यक्ष बने पर 2013 का अगला चुनाव वे हार गये और 2013 में गौरीशंकर अग्रवाल विस अध्यक्ष बने हैं और अगला2018 का चुनाव वे भी हार गये यानि विस अध्यक्ष हारते हैं तो उस पार्टी की सरकार बनती है।2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और डॉ चरणदास महंत विस अध्यक्ष बने,वे इस बार भी चुनाव समर में उतरे हैं।नेता प्रतिपक्ष के साथ ही यही मिथक जुड़ा है कि वे अगला चुनाव हार जाते हैं। छग नया राज्य बना तो नंदकुमार साय पहले नेता प्रतिपक्ष बने पर अगला 2003 का विस चुनाव वे अजीत जोगी से हार गये। 2003 में महेन्द्र कर्मा नेता प्रतिपक्ष बने पर 2008 का विस चुनाव वे हार गये।2008 में रविंद्र चौबे नेता प्रतिपक्ष बने पर 2013 का विस चुनाव वे हार गये उन्हें अपने जीवन में पहली बार चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था। 2013 में टीएस सिंहदेव को नेता प्रतिपक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई है पर वे चुनाव में इस मिथक को तोड़ते हुए 2018 का चुनाव जीत गये है।2018 के विस चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष दो लोग बने धरमलाल कौशिक और उनके बाद नारायण चंदेल... मौजूदा चुनाव में दोनों चुनाव समर में हैं,3 को मतगणना में क्या होता है यह देखना है?पंचायत मंत्री भी अगला चुनाव हार जाते हैं। नया राज्य बनने के बाद अजीत जोगी के कार्यकाल में अमितेष शुक्ला पंचायत मंत्री बने पर अमितेष शुक्ला अगला चुनाव हार गये। भाजपा की पहली सरकार बनी और अजय चंद्राकर पंचायत मंत्री बने पर उन्हें भी अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद रामविचार नेताम पंचायत मंत्री बने बाद में हेमचंद यादव को पंचायत मंत्री बनाया गया पर 2013 के चुनाव में दोनों हार गये। बाद में अजय चंद्राकर पंचायत मंत्री बने उन्होंने मिथक तोड़ते अगला चुनाव जीता पर सरकार कॉंग्रेस की बनी।नये राज्य में महिला एवं बाल विकास मंत्री भी अगले चुनाव में पराजित हो जाती हैं। अजीत जोगी की सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी को बनाया गया था पर 2003 का चुनाव और 2004 के उप चुनाव में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा।भाजपा की पहली सरकार में रेणुका सिंह तथा दूसरी सरकार में लता उसेंडी इस पद पर रहीं पर अगले चुनाव में इन्हें भी पराजित होना पड़ा। रमन सिंह की तीसरी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री के पद पर रमशीला साहू पदस्थ हुई थी पर,उन्हें तोअगले चुनाव में टिकट ही नहीं दी गई।भूपेश की सरकार में अनिला भेड़िया को महिला एवं बालविकास मंत्री बनाया गया,वे भी इस बार चुनाव समर में हैं....?

मप्र की कार्यवाहक सीएस वीरा राणा रायपुर में भी रह चुकी हैं पदस्थ....

मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इस रेस में सबसे आगे 1988 बैच की आईएएस अधिकारी वीरा राणा चल रही हैं। उन्हें चुनाव आयोग ने कार्यवाहक मुख्य सचिव बना दिया है,हालांकि उनके सीएस बनने पर अंतिम मुहर मप्र की नई सरकार लगाएगी।यहाँ यह बताना जरुरी है

कि श्रीमती वीरा संजय राणा अविभाजित मप्र में रायपुर में एडीशनल कलेक्टर रह चुकीं हैं तो इनके पति 1986 बैच के आईपीएस संजय राणा रायपुर के पुलिस कप्तान भी रह चुके हैं।दरअसल मप्र के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो गया।ऐसे में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ आईएएस वीरा राणा को कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाने का आदेश जारी कर दिया है।वीरा राणा 1988 बैच की आईएएस अफसर हैं।वीरा राणा मूल रुप उप्र की रहने वाली हैं अगर राणा पूर्णकलिक मुख्य सचिव बनती हैं तो वे मप्र शासन की दूसरी महिला होंगी जो मुख्य सचिव बनेंगी।इनसे पहले निर्मला बुच मप्र की पहली महिला मुख्य सचिव रह चुकी हैं।इनका कार्यकाल 22 सितंबर 1991 से एक जनवरी 1993 तक था।

महंगी यात्रा और बार- बार रेल भी होती है रद्द..

पहले कहा जाता था कि रेल की आग (कोयला इंजन)जेल की आग (जेल के भीतर रसोई घर) कभी नहीं बुझती है यानि रेल रोजाना चलती हैऔर जेल की रसोई में भी रोज खाना बनता ही है पर,कोरोना काल में रेल बंद की गई और उसके बाद तो कभी आधुनिकता, कभी सुधार के नाम पर कभी भी रेल बंद कर दी जाती है।कोरोना के बाद कुछ रेलों में यात्री किराया बढ़ाया गया वह अभी भी चल रहा है।बुजुर्गो सहित अन्य वर्गो,महिलाओं को भी यात्रा में दी जाने वाली छूट भी समाप्त कर दी गई, सांसदों, विधायकों की छूट जारी है...? छग में ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं। ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला करीब साल भर से चल रहा है। किसी न किसी कारण से रेलवे लगातार गाड़ियों को रद्द कर रहा है।इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी होती रही है पर ट्रेनों के रद्द होने का क्रम बदस्तूर जारी है। छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में यूपी-बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ा झटका लगा है।उत्तर पूर्व रेलवे की ओर से सारनाथ एक्सप्रेस को 2 दिसम्बर 2023 से 29 फरवरी 2024 के बीच कई तारीखों को रद्द की गई है। रेलवे इसके पीछे की वजह कोहरे की आशंका को बता रहा है। यहाँ यह बताना जरुरी है कि प्रयागराज सीधे जाने वाली सारनाथ एक मात्र रेल है।खैर छग से होकर चलने वाली 18 ट्रनों को भी रद्द किया गया है।यह काम 27 नवंबर 2023 से 23 मार्च 2024 तक किया गया है।इन ट्रेनों के रद्द होने के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर स्टेशन से उत्तर प्रदेश जाने वाले कई ट्रेनें रद्द रहेगी। इससे रेल यात्रियों कोकाफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।सवाल यहीं उठ रहा है कि निम्न,माध्यमवर्गीय लोग क्या करेंगे .... वह तो टैक्सी या विमान से यात्रा करने में समर्थ नहीं है?

छग विस परिणाम, सबसे पहले, सबसे बाद में कौन.....

कवर्धा, कसडोल, पंडारिया,सारंगढ़, जशपुर,बिल्हा और मस्तूरी विधानसभा सीट का परिणाम सबसे देर से आएगा। यहां के लोगों को इस बात का लंबा इंतजार करना पड़ेगा कि उनके क्षेत्र का विधायक कौन बना। जानकारी के अनुसार कवर्धा सीट में 29 राउंड में मतगणना होगी।कसडोल में भी 29 राउंड में होगी। वहीं,पंडरिया सीट में वोटों की गिनती 28 राउंड में पूरी होगी।इधर मनेन्द्रगढ़ सीट में वोटों की गिनती सबसे पहले होगी क्योंकि यहां गिनती 11 राउंड में होगी।उसके बाद भिलाई नगर सीट में 12 राउंड में गिनती पूरी होगी। मनेन्द्रगढ़ और भिलाई नगर के अलावा रायपुर उत्तर,बस्तर,दुर्ग शहर, पामगढ़, जांजगीर ,दुर्ग ग्रामीण, बिलासपुर, राजनांदगांव सीट के परिणाम सबसे पहले आएंगे?

और अब बस.....

- रायपुर की चारों विस सीटों में जीत-हार को लेकर सबसे अधिक शर्त लगाई जा रही है?
- कांग्रेस में एक युवा आदिवासी नेता भी सीएम बनने का सपना देखने लगे हैं ?
- देखना है कि कितने बड़े नेता पुनऱ्चुनकर आते हैं?

नारायण ने कहा एक्जिट पोल मात्र आकलन है, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा

00 तीन दिसंबर को तो उनकाकांग्रेस का सत्ता में लौटने का सपना चूर-चूर हो जायेगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। श्री चंदेल ने कहा कि जनता ने इस बार के चुनाव में बदलाव के लिए जनादेश दिया है और अब सी-एम (सी यानी कांग्रेस और एम यानी माओवाद) वालों सरकार से छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिलेगी।

उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 7 और 17 नवंबर को हुए मतदान के सर्वे की रिपोर्ट्स (एग्जिट पोल) विभिन्न एजेंसियों और चैनलों पर सार्वजनिक होने के बाद अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि यह जो सर्वे है, वह मात्र आकलन है। हमारा आकलन है और हमारा यह सुस्पष्ट मत है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और भूपेश सरकार के कुशासन की विदाई चाहती है। जनता का आशीर्वाद, स्नेह और प्यार भाजपा को प्राप्त होगा और छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में वोट शेयर का जो 10 फीसदी का अंतर था, वह इस बार के चुनाव में कांग्रेस के लिए कतई फायदेमंद साबित नहीं होगा और इसके चलते कांग्रेस भारी नुकसान उठा रही है।

चंदेल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और भाजपा के घोषणा पत्र मोदी की गारंटी ने भाजपा के प्रति जन-विश्वास को दृढ़तर किया है और पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ।

भाजपा की महतारी वंदन योजना को प्रदेश की मातृ-शक्ति का अच्छा प्रतिसाद मिला है।

भिलाई स्टील प्लांट में स्टीम बॉयलर में लगी आग, मौके पर मची अफरा-तफरी

दुर्ग. भिलाई इस्पात संयंत्र के पीपी वन डिपार्टमेंट के स्टीम बॉयलर आग लग गई. आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के मुताबिक केबल जलने से पीपी वन के स्टीम बॉयलर में आग लगी. हालांकि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है. बता दें कि बीएसपी में लगातार दूसरे दिन हादसा हुआ है. इसके पहले गुरुवार को भी बीएसपी के लोको रिपेयर शॉप में एक मजदूर पैर फिसलने से गिर गया था. चोट लगने की वजह से उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एक्जिट पोल के आंकड़ों को झुठलाने में लगे कांग्रेस, भाजपा

रायपुर। तमाम सर्वे एजेंसियों की एक्जिट पोल रिपोर्ट मतगणना से दो रोज पहले आते ही राजनैतिक दल आकड़ों को लेकर सक्रिय हो गए है। सर्वे रिपोर्ट में जहां कांग्रेस को सभी में भाजपा की अपेक्षा दस सीटों तक बढ़त दिखाई गई है वही भाजपा की सीटें भी पहले की अपेक्षा दोगुने से अधिक नजर आ रही है। इसके बाद अब दोनों ही पार्टियां अपने-अपने हिसाब से एक्जिट पोल का मानमर्दन कर रही है। कांग्रेस जहां और अधिक सीटें आने का दावा कर रही है वही भाजपा को सत्ता के करीब होने की खुशबू आ रही है। सभी सर्वे के औसत में कांग्रेस को 49 और भाजपा को 38 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले विभिन्न एग्जिट पोल में कांटे का टक्कर दिखाने के बाद से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों सतर्क हो गई हैं। उन्होंने अपने भाभी विधायकों को एकजुट रखने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार यदि परिणाम करीबी रहे तो कांग्रेस अपने जीते हुए प्रत्याशियों को बेंगलुरु भेज सकती है इसके लिए उसने 72 सीटर चार्टर्ड प्लान भी बुक कर लिया गया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

शराब की आपूर्ति में कचरा और कीड़ा पाए जाने पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही

रायपुर। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के दो डिस्टलरीयों द्वारा देशी शराब (प्लेन-पाव) की आपूर्ति में कचरा व कीड़ा पाए जाने पर पीने के लिए हानिकारक मानते हुए संबंधित के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। इन दोनों डिस्टलरीयों द्वारा आपूर्ति की गई 7189 पेटी देशी शराब प्लेन पाव को जप्त कर नष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दोनों डिस्टलरीयों के मेसर्स पर वर्तमान शराब मूल्य की राशि 2 करोड़ 75 लाख 66 हजार 480 रूपए का जुर्माना लगाते हुए यह राशि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड में जमा करने को कहा गया है। इनमें मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-छेरकाबांधा, जिला- बिलासपुर को 2 करोड़ 29 लाख 27 हजार 440 रूपए और मेसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड, ग्राम-खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग को 46 लाख 79 हजार 40 रूपए जमा करने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मेसर्स वेलकम डिस्टलरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-छेरकाबांधा, जिला- बिलासपुर के द्वारा जिला जांजगीर-चांपा में प्रदाय की गई देशी मदिरा प्लेन के पाव में कचरा एवं कीड़ा पाये जाने की शिकायत की जांच पर बैच नंबर 141, 145 एवं 156 के अंतर्गत भरी गई.

अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई, एक की मौत

रायपुर। राजधानी रायपुर की सड़कों पर एक बार फिर रफ्तार का कहर दिखा। आधी रात को रिंगरोड पीडब्ल्यूडी ब्रिज पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर की रेलिंग से टकरा गई। तेज रफ्तार कार की डिवाइडर से इतनी जोर से टक्कर हुई कि कार के परखच्चे उड़ गए और इंजन बाहर निकल आया।

इस हादसे में कार सवार युवक देवकुमार साहू (18 साल) की मौके पर मौत हो गई। जबकि दूसरा युवक ओंकार साहू (19 साल) बुरी तरह घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज जारी जारी है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।

दरअसल, यह मामला सिविल लाइन थाना इलाके का है। सिविल लाइन थाना की पुलिस ने बताया कि रिंगरोड पीडब्ल्यूडी ब्रिज पर एक हादसे की खबर मिली है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को वहां एक कार दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिले।

प्राथमिक जांच में पता चला कि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार में सवार दो लोग सवार थे, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

निज़ामुद्दीन-रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस कई दिन रहेगी रद्द

रायपुर। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मण्डल के भोपाल-इटारसी रेल खंड पर बुदनी-बरखेड़ा (घाट सेक्शन) के मध्य तीसरी लाइन चालू करने के सम्बंध में बुदनी, मिडघाट, चौका एवं बरखेड़ा स्टेशनों पर प्री नॉन/नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है । जिसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने/गुजरने वाली कुछ गाडियाँ प्रभावित रहेगी।

रद्द होने वाली गाडियां- 6 एवं 07 दिसम्बर निज़ामुद्दीन-रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस, 8 एवं 9 दिसम्बर को रायगढ़-निज़ामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस, 6-7 एवं 8 दिसम्बर को कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, 8, 9 एवं 10 दिसम्बर को अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और 6 से 8 दिसम्बर तक बिलासपुर-कोरबा पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

100 किलो कबाड़ से तैयार 8 फीट की राजकीय पक्षी शहर की बढ़ा रही शोभा

रायपुर। राजधानी में छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की विशाल प्रतिमा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इस पहाड़ी मैना की प्रतिमा रायपुर के महात्मा गांधी सदन नगर निगम मुख्यालय के सामने लगाई गई है. पहाड़ी मैना को 100 किलो कबाड़ से तैयार किया गया है, जो 8 फीट ऊंची है.

संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक पहाड़ी मैना को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता लाने यंग इंडिया ग्रुप रायपुर चेप्टर ने यह प्रयास किया है. शहर को सुंदर बनाने और शहर को सुंदर बनाने पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने पहाड़ी मैना की सुंदर आकृति स्थापित की गई है. पहाड़ी मैना की प्रतिमा तैयार करने फैक्ट्री और घरों से निकलने वाली अनुपयोगी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. इसमें सरिया, गियर प्लेट, मशीनों के क्षतिग्रस्त हिस्से, लोहे की चेन, जाली, लोहे की प्लेट आदि का उपयोग किया गया है. नगर निगम रायपुर और यंग इंडिया ग्रुप रायपुर चेप्टर सहित कई संस्थाओं के सहयोग से सुंदर पहाड़ी मैना को तैयार किया गया है. आकृति का मेंटेनेंस यंग इंडिया ग्रुप रायपुर चेप्टर और हीरा ग्रुप द्वारा किया जाएगा. राजकीय पक्षी के बारे नई पीढ़ी को बताने और कबाड़ से जुगाड़ की थीम पर विलुप्त होते पक्षियों को बचाने की पहल की आमजनों द्वारा सराहना भी की जा रही है.

लाईफस्टाईल बदलने से बच्वें में हो रही आटिज्म बीमारी-डॉ. औजला

रायपुर। पीडियाट्रिक न्यूरोलाजिस्ट डॉ आशीष सिंह औजला ने बताया कि बच्चों में आटिज्म (आत्मकेन्द्रित) नामक बीमारी बीते सात आठ सालों में तेजी से बढ़ रही है। यह बीमारी पहले केवल विदेशों में थी लेकिन अब भारत में भी तेजी से पांव पसार रही है। डॉक्टर औजला ने बताया कि इस बीमारी की प्रमुख वजह लोगों के लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आना है। बच्चे ज्यादा टीवी देखते हैं या मोबाइल में लगे रहते हैं इस वजह से उन्हें एक्स्पोज़र मिल रहा है। इस कारण से यह बीमारी अधिक फैल रही है। बीमारी से बचाव एवं उपचार के लिए सावधानी रखना और डायग्नोसिस मुख्य उपाय हैं। न्यूरोलाजिस्ट डाक्टर औजला ने बताया कि ऑटिज्म के अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो सही बोलते नहीं है और जिन्हें व्यवहार संबंधी समस्या होती है। यह समस्या बच्चे में डेढ़ से दो साल के भीतर दिखना शुरू हो जाती है। इसका इलाज जितना जल्दी हो सके शुरू किया जाना चाहिए। ऑटिज्म थेरेपी का इलाज महंगा जरुर है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। आम आदमी इसे एफर्ट कर सकता है। इसके पीछे वजह प्रत्येक पेशेंट या बच्चे को अलग से ट्रीटमेंट देना है। इसका प्रारंभिक स्टेज में ही उपचार होना बेहतर है टीवी मोबाइल से बच्चे दूर रहे तो ही ठीक है। बच्चों के चिकित्सक ने बताया कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश में एक दो जगह चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर खुले है.

अभा सिक्ख प्रीमियर लीग क्रिकेट का उद्घाटन मैच खालसा वारियर्स नांदेड़ ने जीता

रायपुर। 15 वीं सिक्ख प्रीमियर लगेज 2023 आल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। एसईसीआरएसए क्रिकेट ग्राउंड डब्ल्यूआरएस कालोनी में उद्घाटन मैच विजित खालसा नागपुर व खालसा वारियर्स नांदेड़ के बीच खेला गया। नांदेड़ की टीम ने शानदार जीत दर्ज कराई. दूसरा मैच शहीद भाई तारु सिंघ स्टडी सर्कल रायपुर व चैलेंजर्स इलेवन तेलंगाना के बीच खेला गया जिसमें रायपुर की टीम जीती। कुल 12 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में बतौर अतिथि विधायक कुलदीप जुनेजा,राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र छाबड़ा व एसजीपीसी छत्तीसगढ के अध्यक्ष गुरमीत सिंग सैनी उपस्थित थे।

राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष ने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि स्टार्टअप्स कार्यक्रम के उद्यमियों से चर्चा की

छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित स्टार्टअप्स हेतु असीम संभावनाएं - ढांड

रायपुर। राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष श्री विवेक ढांड ने आज यहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं रफ्तार एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन योजना के अंतर्गत संचालित कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत स्थापित नवीन स्टार्टअप्स उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि आधारित व्यवसायों में स्टार्टअप्स स्थापित करने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि कृषि का क्षेत्र काफी वृहद होने के कारण इस पर आधारित अनेक स्टार्टअप्स शुरू किये जा सकते हैं। श्री ढांड ने आई.जी.के.वी.-राबी कार्यक्रम के तहत स्थापित विभिन्न स्टार्टअप्स उद्यमियों के साथ चर्चा कर उनके द्वारा किये जा रहे कार्यां तथा उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्टार्टअप्स और नवाचार के क्षेत्र में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे कार्यां की सराहना की तथा कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल एवं स्टार्टअप्स कार्यक्रम के जुड़े सभी अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्री ढांड ने इस अवसर पर कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्टअप्स प्रारंभ करने हेतु राज्य नवाचार आयोग द्वारा हर संभव

सहयोग किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न सृ्टाटअप्स द्वारा तैयार किये जा रहे उत्पादों का भी अवलोकन किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कृषि आधारित स्टार्टअप काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनसे बहुत से लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर स्टार्टअप की अपनी एक सफलता की कहानी है जो और लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि अन्य लोग भी कृषि आधारित स्टार्टअप की स्थापना के लिए आकर्षित हो सकें। डॉ. चंदेल ने कहा कि इन स्टार्टअप के माध्यम से कृषि आधारित 900 से अधिक उत्पाद निर्मित किये जा रहे हैं जिनसे लाखों किसानों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है उन्होंने कृषि छात्रों से आव्हान किया कि वे कृषि आधारित स्टार्टअप्स स्थापित करने के लिए आगे आएं। आई.जी.के.वी. राबी कार्यक्रम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. हुलास पाठक ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत विगत चार वर्षां में 236 स्टार्टअप्स प्रवेशित हुए हैं, जिनमें से 101 स्टार्टअप्स को भारत सरकार की ओर से 10.84 करोड़ का आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है।

निधन

रीतारानी देवांगन

रायपुर। पार्थिवी नगर, महोबा बाजार निवासी श्रीमती रीतारानी देवांगन (66 वर्ष) का शुक्रवार 01 दिसंबर को निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास से सुबह 11 बजे महादेव घाट मुक्तिधाम के लिए रवाना होगी। वो डॉ गोपाल प्रसाद देवांगन की पत्नी, रवि, आकाश देवांगन एवं कंचन महेश ठाकुर की माता थीं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.